लखनऊ

रविवार 18 जनवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 149

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

कोई भी कठिनाई क्यों न हो, अगर हम सचमुच शान्त रहें तो समाधान मिल जाएगा।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi

NIGHT 10° Low

'जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां संगीत', बोले- राज्य बना रहा नई पहचान

बंगाल में अब नहीं चलेगा टीएमसी का तुष्टिकरण, मालदा रैली से पीएम मोदी का सीधा संदेश

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्वी भारत दशकों से घृणा की राजनीति के कारण पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति विकास को रोकती है और लोगों को अवसरों से वंचित करती है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए विकास-केंद्रित शासन आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्वी भारत का विकास आवश्यक है। मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास एक 'विकसित भारत' के निर्माण की कुंजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवेंदु शेखर राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मालदा की पहचान को संरक्षित करने में उनके प्रयासों की सराहना की। एक जनसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लिए राय के योगदान को स्वीकार किया और स्थानीय विरासत को विकास और सांस्कृतिक गौरव की व्यापक कहानी से जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और हिंसा की पार्टी के रूप में बेनकाब हो चुकी है। मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को ऐसी भाजपा सरकार की जरूरत है जो विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी पार्टी पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने पूर्वी राज्यों को विभाजनकारी और नफरत से प्रेरित राजनीति के चंगुल से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान विकास, अवसंरचना निर्माण और जन कल्याण पर केंद्रित है, और उन्होंने जोर देकर कहा कि इन प्रयासों से पूर्वी भारत देश की विकास गाथा में और अधिक मजबूती से जुड़ रहा है।

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में आयोजित बोडो समुदाय के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'बागुरुम्बा द्वौ 2026' में भाग लिया, जहां उन्होंने पारंपरिक वाद्य यंत्र 'सेर्जा' बजाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ मिलकर बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि असम की संस्कृति, यहां की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी बार मैं असम आया हूं, पहले कोई और पीएम इतनी बार नहीं आया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि असम की कला और संस्कृति को बड़ा मंच मिले। भव्य आयोजनों के जरिए इसकी पहचान देश और दुनिया में बने। इसके लिए पहले भी लगातार प्रयास होते रहे हैं। बड़े स्तर पर बिहू से जुड़े आयोजन हों, दिल्ली में सवा साल पहले हुआ भव्य बोडोलैंड महोत्सव हो या दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम हों। असम की कला और संस्कृति में जो अद्भुत आनंद है, उसे पाने का मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं।

मोदी ने कहा कि बागुरुम्बा दहोउ, ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये एक माध्यम है, हमारी महान बोडो परंपरा को सम्मान देने का। ये एक माध्यम है, बोडो समाज की महान विभूतियों को याद करने का। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार, असम की हर विरासत, हर गौरव का सम्मान अपना सौभाग्य समझती है। संयोग से आज ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि असम का आत्मविश्वास, असम का सामर्थ्य और असम की प्रगति से भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई शक्ति मिल रही है। आज असम तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। असम की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। इस विकास में, इस बदलाव में बोडोलैंड और यहां के लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यह सोचकर भावुक हो रहा हूं कि मेरा असम कितना आगे बढ़ रहा है। एक समय, जहां आए दिन रक्तपात होता था, आज वहीं संस्कृति के अद्भुत रंग सज रहे हैं। एक समय, जहां गोलियों की गूंज थी, आज वहां खाम और सिफुंग की मधुर ध्वनि है। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज वहां संगीत के सुर गूंज रहे हैं। पहले जहां अशांति और अस्थिरता थी, आज वहां बागुरुम्बा की ऐसी प्रस्तुतियां होने जा रही हैं। ये उपलब्धि सिर्फ असम की नहीं है, पूरे भारत की है। असम के इस बदलाव पर हर देशवासी को गर्व है। मोदी ने कहा कि 2020 के बोडो शांति समझौते ने वर्षों से चले आ रहे संघर्ष पर विराम लगाया। इस समझौते के बाद भरोसा लौटा... और हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा को अपना लिया। प्रतिभाशाली बोडो युवा आज असम के सांस्कृतिक दूत बन रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी बोडो समाज के बेटे-बेटियां नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम असम की कला, संस्कृति और पहचान का सम्मान करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं।

सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, 'काशी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस फैला रही एआई वीडियो का झूठ'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय द्वारा पूजनीय शाश्वत नगरी काशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-11.5 वर्षों में अभूतपूर्व पुनरुत्थान देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि काशी की प्राचीन आध्यात्मिक पहचान को संरक्षित करते हुए इसे एक आधुनिक वैश्विक धरोहर शहर में रूपांतरित करने के लिए 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की व्यापक विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस प्रक्रिया में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय जीडीपी में इसका 1.3 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण योगदान है।

योगी ने कहा कि काशी अविनाशी है। प्रत्येक भारतीय काशी के प्रति असीम श्रद्धा रखता है, लेकिन स्वतंत्र भारत में काशी को जिस व्यापक विकास कार्यक्रम का सम्मान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। पिछले 11-11.5 वर्षों में काशी ने भौतिक विकास कार्यों के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूते हुए अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक बार फिर संरक्षित और बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। उन्होंने शुरू से ही इस विषय पर कहा है कि काशी के प्राचीन स्वरूप को संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे देश और दुनिया के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इसी के अनुरूप पिछले 11-11.5 वर्षों में काशी के लिए योजनाएँ शुरू की गईं।

मुख्यमंत्री योगी ने आगे बताया कि काशी के लिए 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 36,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, और शेष योजनाएँ तेजी से आगे बढ़ रही हैं... 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम के अस्तित्व में आने से पहले, यहाँ प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,000 से लेकर केवल 25,000 तक थी। आज, उसी काशी में प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु आते हैं... अकेले काशी ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है। AI वीडियो बनाकर गुमराह करने के प्रयास हो रहा है। सनातन की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं, वे इस प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा बनेंगे क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो काशी की विरासत को हमेशा बदनाम करने में लगे रहते हैं। उसे अपमानित करते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की।

संक्षेप

एआर रहमान के कम्युनल वाले बयान पर भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं-आप जैसा घृणित व्यक्ति नहीं देखा

मुंबई। संगीतकार एआर रहमान फिल्मी सिनेमा को कम्युनल कहकर बुरे फंस चुके हैं। उन्हें अपने बयान की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एआर रहमान को पूर्वाग्रही और बुरा इंसान बताया है। अभिनेत्री ने एक घटना का भी जिक्र किया है, जिसमें संगीतकार ने अभिनेत्री की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। एआर रहमान को लेकर बढ़ते विवाद पर अब कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा, डियर, एआर रहमान, फिल्म उद्योग में मुझे भगवा पार्टी का समर्थन करने के कारण बहुत भेदभाव और पक्षपात का सामना करना पड़ता है, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपसे अधिक पूर्वाग्रही और हेटफुल व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने लिखा, मैं आपको अपनी फिल्म इमरजेंसी की कहानी सुनाना चाहती थी, लेकिन कहानी सुनाने की बात तो दूर, आपने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। मुझे बताया गया कि आप प्रचार फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते। विडंबना यह है कि इमरजेंसी को सभी आलोचकों ने उत्कृष्ट कृति बताया, यहां तक कि विपक्षी दल के नेताओं ने भी फिल्म की सराहना करते हुए मुझे प्रशंसा पत्र भेजे, लेकिन आप अपनी नफरत से अंधे हो गए हैं। मुझे आपके लिए खेद है। कंगना रनौत पहली व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी हो। सिंगर शान ने भी सिंगर एआर रहमान के बयान को गलत बताते हुए कहा कि ये किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सिनेमा में मुझे भी कुछ समय काम नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसे पर्सनली नहीं लिया, क्योंकि काम मिलना या न मिलना हमारे हाथ में नहीं है। काम कब मिलना है और कितना मिलना है, ये हमारी पहुंच से दूर है। हम बस अच्छा काम कर सकते हैं।

महाराष्ट्र निकाय चुनाव : हार के बाद ईवीएम पर सवाल, नाना पटोले बोले- बैलेट पेपर का होना चाहिए इस्तेमाल

मुंबई ,17 जनवरी (आरएनएस)। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने मांग उठाई है कि राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नाना पटोले ने कहा कि ईवीएम से भरोसा उठ गया है। नगर निगम चुनावों में हुई गड़बड़ी की वजह से चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा कम हुआ है। वीवीपैट का इस्तेमाल न होना पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह चुनावी उदासीनता नहीं, बल्कि प्रशासनिक अक्षमता है। उन्होंने चि_ी में कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल फिर से शुरू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने चि_ी में लिखा, 29 नगर निगमों के चुनावों ने महाराष्ट्र में चुनावी सिस्टम की पोल पूरी तरह से खोल दी है। शहरी इलाकों में बहुत कम मतदान प्रतिशत सिर्फ वोटर की बेपरवाही की निशानी नहीं है।

11 साल में 55 हजार करोड़ से काशी को मिली नई पहचान, देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान

आर्यावर्त क्रांति

वाराणसी। सुबह की पहली ट्रेन जब वाराणसी जंक्शन पर रुकती है, तो प्लेटफॉर्म पर उतरते यात्रियों की आंखों में एक अलग-सी चमक होती है। कोई पहली बार आया है, कोई वर्षों बाद। लेकिन एक बात सब महसूस करते हैं- यह वही काशी है, फिर भी पहले जैसी नहीं। करीब 11 साल पहले की बात याद करें, तब काशी की गलियां तंग थीं।

दर्शन कठिन थे और श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। एक दिन में 20–25 हजार लोग आ जाएं, तो शहर पर दबाव साफ दिखने लगता था। आज वही काशी रोज औसतन सवा लाख से डेढ़ लाख श्रद्धालुओं को संभाल रही है। सावन, शिवरात्रि या बड़े पर्वों पर यह संख्या छह से 10 लाख तक पहुंच जाती है। पिछले एक साल में ही 11 करोड़ से अधिक लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहां आए। इस बदलाव की नींव आंकड़ों में छुपी है, लेकिन इसकी असली कहानी लोगों की ज़िंदगी में दिखती है। बीते 11 वर्षों में काशी के लिए 55 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। इनमें से करीब 36 हजार करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। सड़कें चौड़ी हुईं। घाट संवरें। कनेक्टिविटी सुधरी और दर्शन की व्यवस्था बदली। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो कई लोगों को सिर्फ पत्थर और इमारतें दिखीं।

लेकिन स्थानीय दुकानदार, नाविक और पुरोहितों के लिए इसका मतलब था- सम्मानजनक रोजगार और स्थिर आमदनी। आज फूल-प्रसाद बेचने वाले से लेकर होटल कर्मचारी तक, हजारों परिवारों की आजीविका सीधे-सीधे इस बदलाव से जुड़ी है।

पानी, हवा और दवा में ज़हर, जवाब मांगो तो चलेगा बुलडोजर : इंदौर त्रासदी पर राहुल गांधी का भाजपा सरकार पर तीखा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भाजपा के स्मार्ट सिटी मॉडल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इस व्यवस्था में गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है और जवाबदेही मांगने पर बुलडोजर की धमकी दी जाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्क (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को घेरा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा - क्चछ्वक्क की डबल इंजन सरकार का नया स्मार्ट सिटी मॉडल—पानी में ज़हर, हवा में ज़हर, दवा में ज़हर, ज़मीन में ज़हर, और जवाब मांगो तो चलेगा

बुलडोजर! कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस प्रशासनिक मॉडल में लापरवाही से होने वाली मौतों के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। उन्होंने इंदौर की घटना को सरकारी लापरवाही करार दिया।

इंदौर त्रासदी : मुआवजे और न्याय की मांग

हाल ही में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में सीवेज मिला दूषित पानी पीने से कई लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हैं। इस मानवीय त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए राहुल गांधी ने सरकार से तीन प्रमुख मांगें की हैं:

जवाबदेही तय हो : इंदौर त्रासदी की जिम्मेदारी सरकार तुरंत स्वीकार करे।

दोषियों को सजा : लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और ज़िम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मुआवजा और इलाज: पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और उनके परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए।

गरीबों की मौतों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं

राहुल गांधी ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के शासन में गरीब बेबस है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जनता बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी और शुद्ध हवा की मांग करती है, तो प्रशासन समाधान देने के बजाय दमनकारी नीतियों का सहारा लेता है।

क्या है इंदौर जल संकट?

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी की शुरुआत में पेयजल पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने से डायरिया का भीषण प्रकोप फैला। आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा कम बताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निवासियों और विपक्षी दलों का दावा है कि इस लापरवाही के कारण अब तक 15 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (ह्नत्रञ्ज) ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है।

भाजपा पर 'धोखे' का आरोप, हार के बाद भी उद्धव ठाकरे को भरोसा- ईश्वर की इच्छा से मुंबई में होगा अपना मेयर

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव 'धोखे' से जीता है और वह मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुंबईवासी इसे कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि, ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी 'ईश्वर की इच्छा से' मुंबई में अपना महापौर नियुक्त करेगी। भगवा पार्टी द्वारा उनकी पार्टी से बीएमसी छीनने के एक दिन बाद मुंबई के शिवसेना भवन में शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को लगता है कि उसने शिवसेना (यूबीटी) को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने हर संभव प्रयास किया लेकिन वफादारी नहीं खरीद सकी।

भाजपा-शिवसेना गठबंधन द्वारा ठाकरे परिवार से बीएमसी की सत्ता छीनने के एक दिन बाद, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना (उबाठा)कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा मुंबई को गिरवी रखना चाहती है और उसने धोखे से चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष इस 'पाप' को कभी माफ नहीं करेंगे। ठाकरे ने कहा कि मुंबई में शिवसेना(उबाठा) का महापौर बनाना उनका सपना है, और अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो यह सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह गलतफहमी है कि उसने शिवसेना(उबाठा) को खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को भाजपा जमीनी स्तर पर खत्म नहीं कर सकी।' प्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा बीएमसी चुनावों में शिवसेना (उबाठा) द्वारा जीती गई 65 सीटों की ओर था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा निष्ठा खरीदने के लिए साम-दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही है। ठाकरे ने कहा, ''उसने (भाजपा ने) मुंबई को गिरवी रखकर विश्वासघात के जरिए जीत हासिल की है। मराठी मानुष इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरू हुई है।'' बीएमसी के 227 सदस्यीय सदन में भाजपा ने 89 सीट जीतीं हैं, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 29 सीट अपने नाम की है। वहीं, शिवसेना(उबाठा) को 65 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना(मनसे)को छह सीट मिलीं।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात, कई मुद्दों पर विस्तार से हुई चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पंजाब से जुड़े कई संवेदनशील और अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में तार पार सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं से लेकर बीज बिल, जल विवाद, खाद्य सुरक्षा और किसानों से जुड़े विभिन्न विषय प्रमुख रूप से उठाए गए। मुलाकात के दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। ऐसे में बिना पंजाब सरकार से परामर्श किए संसद में बीज बिल लाए जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई। इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा गया कि किसी भी कृषि कानून या बीज से संबंधित विधेयक को लागू करने से पहले पंजाब जैसे कृषि राज्य की सहमति और सुझाव लेना अनिवार्य होना चाहिए। बैठक में सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। इसके अलावा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) में जनरल मैनेजर (जीएम) के पद पर पंजाब कैडर के अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की।

जीवन में संतुलन बनाए रखने, सुख-शांति व समृद्धि के लिए तुलादान का पुण्य लाभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पुत्र-पौत्रादि और धन-धान्य से सम्पन्न व्यक्ति माघ के पावन महीने में ख़ुशी-ख़ुशी मां गंगा-यमुना व अन्य पवित्र नदियों के तट और मंदिरों में तुलादान का पुण्य कमा रहे हैं। तराजू यानि तुला को संतुलन बनाने और विश्वास कायम करने का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए तराजू पर व्यक्ति का वजन कर उस वजन के बराबर सामग्री को दान करने को ही तुलादान कहा जाता है। इसीलिए जीवन में संतुलन बनाए रखने की कामना, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए भी तुलादान किया जाता है। तुलादान की सामग्रियों में अन्न, तेल, घी, गुड़, तिल, फल,

सोना-चांदी आदि को शामिल किया जाता है। इन सामग्रियों को जरूरतमंदों, योग्य ब्राह्मण या गौशाला को दान में दिए जाने की परम्परा है।

यमुना जी के तट पर तुलादान के लिए अपने पुत्र मुकेश कुमार शर्मा, बहू विभा शर्मा, पौत्र आदित्य नमन और पौत्री उन्नति प्रिया के साथ दिल्ली से मथुरा पहुंचीं श्रीमती जनक दुलारी शर्मा का कहना है कि वह ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए इस पुण्य को कमाने के लिए आई हैं। ईश्वर का दिया हुआ उनके पास सब-कुछ है अब जीवन में आध्यात्मिक व मानसिक शांति और बच्चों की सुख-शांति व समृद्धि की कामना से तुलादान का पुण्य कमाने आई हैं। इस सुखद अवसर का हर्ष उनके पुत्र-पौत्रादि के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रहा था। विभा मुकेश शर्मा का कहना है कि उन्हें तुलादान के महात्म्य के बारे में अच्छी तरह से पता था और उनकी माता जी की परम इच्छा थी कि वह अपना तुलादान कर इस पुण्य को कमाने का कार्य जरूर करेंगी। यह शुभ अवसर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, जिससे परिवार के हर सदस्य अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि तुलादान करने से यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि का भी पुण्य लाभ मिलता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि समाज में अपनी महती जिम्मेदारियों के निर्वहन का भी प्रतीक है। श्रीमती जनक दुलारी शर्मा तुलादान संपन्न होने के बाद काफ़ी प्रफुल्लित थीं और अपने पुत्र, पुत्रवधू और बच्चों को भावुकता पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। उनका पूरा परिवार देश के विभिन्न हिस्सों से वीडियो कॉल द्वारा पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ। पुत्रवधू के परिवार जन भी दूरभाष द्वारा इसमें शामिल थे।

प्रदेश के मथुरा नगरी में यमुना जी के तट पर स्थित विश्राम घाट के तुला दान मंदिर में तुलादान की प्रक्रिया पूरी करा रहे पंडित गिरिराज का कहना है कि यहाँ पर बहुत से लोग इस माघ महीने में तुला दान का पुण्य कमाते हैं। बहुत से लोग अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ, आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति, सुख-शांति, समृद्धि, किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति, किसी विशेष संकट आदि से उबरने, जन्म कुंडली के दोष निवारण और पापों के नाश के लिए भी तुलादान करते हैं। इस पुण्य को कमाने के लिए माघ महीने, मकर संक्रांति या पूर्णिमा आदि को खास तौर पर शुभ माना जाता है, किन्तु व्यक्ति चाहे तो वर्ष भर में कभी भी तुलादान का पुण्य कमा सकता है।

हैजा माई धाम पर कंबल वितरण व सहभोज का आयोजन

आर्यावर्त संवाददाता

कुड़वार, सुल्तानपुर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सरकौड़ा गांव सभा स्थित हैजा माई धाम परिसर में कंबल वितरण व सहभोज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक राम चंद्र मिश्रा रहे।

कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का आयोजक एवं पूर्व प्रधान अशोक यादव ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राम चंद्र मिश्रा ने कहा कि संगठन में ही वास्तविक शक्ति निहित होती है। यदि समाज संगठित होकर कार्य करे तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। उन्होंने प्रदेश व केंद्र में भाजपा सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही आज देश और प्रदेश में स्थिर व मजबूत

सरकार कार्य कर रही है, जिसकी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। मुख्य अतिथि ने भीषण ठंड के मौसम में जरूरतमंदों के लिए किए गए कंबल वितरण की सराहना करते हुए इसे सराहनीय सामाजिक कार्य बताया। आयोजक की ओर से सरकौड़ा गांव सभा के लगभग 500 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए, जिससे ग्रामीणों में खुशी और संतोष का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर भाजपा नेता रमेश तिवारी, शान, आरडी सिंह, सत्य नारायण पांडेय, राम शंकर मिश्रा, हरिराम पाल, महेश तिवारी, अनिल श्रीवास्तव, अशोक यादव, अवधेश यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने सहभागिता की।

सुंदरकाण्ड भक्ति का मार्ग नहीं, जीवन प्रबंधन का शास्त्र

जौनपुर। लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहि न दूजा।। की पावन चौपाइयों के साथ मृत्युञ्जय महादेव धाम उमरछा में आयोजित सस्वर सुंदरकाण्ड प्रतियोगिता का प्रदोष तिथि का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर निर्मल मानस ग्रुप, औरैला मड़ियाहूं के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत मंत्रमुग्ध कर देने वाले पाठ के उपरांत एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए सुशील कुमार उपाध्याय पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा जौनपुर ने कहा, सुंदरकाण्ड केवल भक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का जीवंत शास्त्र है। निर्मल मानस ग्रुप के युवा कलाकारों ने जिस शुद्धता और लयबद्धता के साथ प्रभु चरित का गान किया है, वह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे आयोजनों से समाज में सनातन मूल्यों का विस्तार होता है। विशिष्ट अतिथि यादवेन्द्र मिश्र और दीपक सिंह श्मोंटीश ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में कहा, ष्कला और भक्ति का संगम जब मंच पर उतरता है।

दबंग पट्टीदारों से परेशान पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार

विपक्षी पर कट्टा और चाकू के साथ घर पर चढ़ाई करने का लगा आरोप

आर्यावर्त संवाददाता

मीरजापुर। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत दूबेपुर चिन्दलिख गांव में एक ही परिवार के दो लोग खेत की मेड़ को लेकर इस तरह भिड़े की मामला कचहरी-कोतवाली के बाद अब घर पर चढ़कर अपराधिक गतिविधियों के आरोप तक जा पहुंचा है। घटनाक्रम की शुरुआत बीते जुलाई माह से आरंभ होकर लगातार जारी है। स्थानीय थाना पुलिस ने भी पैसे वालों की मदद करते हुए चार दिन बाद सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई कर मामले को बढ़ाने का काम किया। मजे की बात यह है कि पुलिस के अधिकारी ने उसपर कार्यवाही की, जिसने सबसे पहले थाने में पहुंचकर घटना की सूचना दी थी, जिसका साक्ष्य पीड़ित अरविन्द अपने झोले में लेकर रोज थाना-कचहरी दौड़ रहा है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़ित ने जो कुछ मीडिया से कहा उसे सुनने वाले का मन भर आया। पीड़ित अरविन्द ने बताया कि उसके और उसके परिवार के साथ बीते 13 जुलाई 25 की सुबह आठ बजे 18 जुलाई 25 को दोपहर तथा अभी पांच दिन पूर्व बीते शुक्रवार 9 जनवरी को एक बड़ी घटना होते होते टल गया, जैसा कि आरोप है। पीड़ित अरविंद कुमार पुत्र रमाशंकर दुबे ने प्रभारी निरीक्षक व पुलिस अधीक्षक को लिखे प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि बीते 9 जनवरी 2026 को शाम लगभग 6 बजे विपक्षी संख्या एक चाकू लेकर पीड़ित के घर चढ़ आया। गालियां देते हुए बाहर बुलाया, बाहर न निकलने पर गला काटकर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी सूचना पर डॉयल 112 की टीम मौके पर गई। पुलिस के जाने के बाद विपक्षी संख्या एक के एक अन्य भाई विपक्षी संख्या 2 भी गुस्से में जा पहुंचे, आरोप है कि उसके हाथ में असलहा था और जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच उनके दो अन्य भाई भी गाली गलौज करते हुए पीड़ित के दरवाजे पर आ धमके। जिसके चलते पीड़ित के घर भय व्याप्त हो गया, लेकिन भला हो उनके पिता का जिन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और अपने तीनों बच्चों को यह कहकर वहां से ले गए कि इसे यहां नही बाहर मारना है। इस प्रकार एक बड़ी घटना होते-होते टल तो गई लेकिन विपक्षी के पिता द्वारा बाहर मारने की धमकी से पीड़ित सहमा हुआ है। पीड़ित ने अपने बयान में ये बाते मीडिया के सामने रखते हुए जान-माल के ख़तरे की आशंका जताई है। पीड़ित अरविंद ने यह भी बताया कि विपक्षी परिवार में दबंग किस्म के लोग हैं, आस पास के लोग गवाही देने से डरते हैं। बताया कि विपक्षी के परिवार से एक अपने को पेशे से अधिवक्ता बताते है, उनके पिता पर थाना देहात कोतवाली में सन 2018 में एक मुकदमा घर में घुसकर महिला से मारपीट सहित जान से मारने का केस संख्या 0369 सन 2018 में तत्कालीन आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 452 दर्ज है। यह प्रकरण शनिवार को तहसील दिवस में भी पहुंचा, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील सदर में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने जांच के आदेश दिए हैं।

जिला विज्ञान क्लब ने किया वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम

आर्यावर्त संवाददाता

सुल्तानपुर। जिला विज्ञान क्लब सुल्तानपुर के तत्वावधान में सनबीम स्कूल सुल्तानपुर में अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और समाज में फैले अंधविश्वासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ शरणजीत कौर, मुख्य अतिथि भूतपूर्व प्रधानाचार्य डॉ राधेश्याम सिंह एवं रिसोर्स पर्सन अंजलि ढाका द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वक्ताओं ने विज्ञान को तर्क, सत्य और प्रगति का मार्ग बताते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया। अंजलि ढाका ने तथाकथित चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। इस अवसर पर पोस्टर, स्लोगन राइटिंग और वर्किंग मॉडल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अंत में अतिथियों ने विद्यार्थियों की सराहना की और वैज्ञानिक सोच अपनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन शैलेन्द्र चतुर्वेदी ने किया तथा प्रधानाचार्या ने सभी का आभार व्यक्त किया।

एशिया की सबसे अमीर नगर निगम में बैठेगा भाजपा का मेयर : सुशील त्रिपाठी

आर्यावर्त संवाददाता

सुल्तानपुर। महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा गठबंधन के सुशासन एवं विकसित भारत के एजेंडे के पक्ष में मतदान किया है।महाराष्ट्र में मुंबई नगर महापालिका के साथ महाराष्ट्र की अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव में 29 में से 25 निगमों में हुई जीत पर शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।भाजपा जिंदाबाद और जीत गए, हम जीत गए, मुम्बई महापालिका जीत गए के नारे लगाए।इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी ने महाराष्ट्र की शानदार जीत पर जनता का आभार जताया।कहा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के ऐतिहासिक चुनाव नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक

नए युग की शुरुआत कर दी है।अब एशिया के सबसे अमीर नगर निगम में तीन दशकों के इंतजार के बाद भाजपा का मेयर बैठेगा।अब

महाराष्ट्र के 29 में से 25 नगर निगमों में भाजपा का मेयर होगा। उन्होंने कहा जनता ने विकसित भारत के पक्ष में मतदान किया है। नकरात्मक राजनीती करने वालों की हार हुई है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर पार्टी मीडिया प्रमुख विजय रघुवंशी ने कहा देश सही दिशा में जा रहा है।विपक्ष के कारनामे गलत है इसीलिए जनता उनको हर चुनाव में सबक सिखा रही हैं।इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष डॉ प्रीति प्रकाश,आशीष सिंह रानू, काली सहाय पाठक,वीरेंद्र भार्गव,सोहनलाल निषाद, मनोज श्रीवास्तव, राम अभिलाष सिंह, सुनील विश्वकर्मा, अतुल सिंह, सतीश सिंह, विनय कुमार सिंह, पूर्व प्रधान दया राम यादव, शिव पूजन निषाद, शिवप्रताप कोरी, पवन मिश्रा, अशोक वर्मा, विनोद मिश्रा आदि मौजूद रहे।

स्कूल जा रहे छात्र को आलू लदी पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। थाना बल्दीराय क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल जा रहे कक्षा 12 के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

जानकारी के अनुसार ग्राम भखरी निवासी बंशराज सिंह का पुत्र युवराज सिंह (17 वर्ष) शनिवार सुबह घर से डीएवी कॉलेज कुमारगंज पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सिंदुरापुर डीह सर्विस लेन से होकर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही आलू लदी पिकअप ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बल्दीराय पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष नारद मुनि सिंह ने बताया कि पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बताया जा रहा है कि युवराज सिंह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। उसकी असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है।

प्रायोगिक ज्ञान पैदा करता है वैज्ञानिक सोच: कुलपति

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर परिसर में विद्यार्थियों को विज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से जोडने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शनिवार को हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित "साइंस बस प्रदर्शनी" का उद्घाटन विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रो. वंदना सिंह द्वारा किया गया। यह साइंस बस प्रदर्शनी विश्वविद्यालय परिसर में एक माह तक संचालित की जाएगी।जिससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को विज्ञान के प्रयोगात्मक और व्यावहारिक पक्ष को नजदीक से समझने का अवसर मिलेगा।साइंस बस प्रदर्शनी में आई.आई.टी. कानपुर की विशेषज्ञ टीम द्वारा विद्यार्थियों को विज्ञान से जुडे विभिन्न प्रयोगों एवं आधुनिक उपकरणों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं सरल तरीके से दी जा रही है। प्रदर्शनी में

टेलीस्कोप, 3-डी प्रिंटर, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से संबंधित अनेक प्रयोगों का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे विद्यार्थी बड़े उत्साह और जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं। इन प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के साथ-साथ उनके वैचारिक और विश्लेषणात्मक कौशल को भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, नवाचार की प्रवृत्ति तथा तार्किक सोच के विकास में प्रायोगिक ज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइंस बस जैसी पहल विज्ञान को पुस्तकों की सीमाओं से बाहर लाकर विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोडती हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय का यह निरंतर प्रयास रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के युवाओं तक विज्ञान की पहुँच सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें अनुसंधान एवं नवाचार के लिए प्रेरित किया जाए। परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि साइंस बस प्रदर्शनी के माध्यम से विश्वविद्यालय परिसर में एक माह तक विज्ञान-प्रचार की गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी, जिसमें विश्वविद्यालय के साथ-साथ क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है । प्रो. अजय प्रताप सिंह, प्रो. मनोज मिश्र, प्रो. गिरिधर मिश्र, प्रो. मिथिलेश सिंह, उप कुलसचिव बबीता सिंह, डॉ. एस. पी. तिवारी, डॉ. धीरेंद्र चौधरी, डॉ. पुनीत धवन, डॉ. काजल डे, डॉ. सुजीत चौरसिया सहित शिक्षक एवं शोधार्थी उपस्थित रहे।

समस्त मतदेय स्थलों पर पढ़ी जायेगी मतदाता सूची

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में अवस्थित 09 विधानसभा क्षेत्रों (364-बदलापुर, 365 शाहगंज, 366-जौनपुर, 367-मल्हनी, 368-मुंगराबादशाहपुर, 369-मछलीशहर, 370-मड़ियाहूं, 371-जफराबाद एवं 372 केराकत) के समस्त मतदेय स्थलों पर ग्रामसभाध्शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के पार्षद ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य ६ बूथ लेविल एजेण्ट ६ स्थानीय प्रतिनिधियों / नागरिकों की उपस्थिति में बी०एल०ओ० द्वारा 18 जनवरी को पूर्वान्ह 10.45 बजे से सायं 4.15 बजे तक मृतक, शिफड, डुप्लीकेट एवं आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जायेगा। यदि किन्हीं कारणों से मृतक, शिफड, डुप्लीकेट में चिन्हित मतदाताओं में से यदि कोई मतदाता उपस्थित पाया जाता है ।

जिला कारागार में बंद युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने उठाए सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिला कारागार में बंद अमेठी के एक युवक की शनिवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है, जबकि परिजनों ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार शैलेंद्र ने शुक्रवार शाम अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की थी और उस समय किसी तरह की तबीयत खराब होने की बात नहीं कही थी। शनिवार सुबह शैलेंद्र के रिश्ते के भाई आशीष सिंह को एसएचओ (धम्मौर) के माध्यम से मौत की सूचना दी गई।आशीष सिंह ने बताया कि जब उन्होंने मौत के

कारण के बारे में पूछा तो उन्हें जेलर से जानकारी लेने को कहा गया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि शैलेंद्र को मृत अवस्था में लाया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी मौत जेल के अंदर ही हुई। परिजनों के मुताबिक शैलेंद्र पिछले 10 महीनों से सुल्तानपुर जिला कारागार में बंद था। आशीष सिंह महीने में दो-तीन बार उससे मिलने जाते थे, जबकि उसकी पत्नी भी हफ्ते में दो दिन मुलाकात करती थी। परिजनों का दावा है कि शैलेंद्र पूरी तरह स्वस्थ था,उसे कोई बीमारी नहीं थी और वह हमेशा अपनी अच्छी सेहत की बात करता था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

यूपी में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कार्य पूरा होने में देर नहीं लगती: मुख्यमंत्री योगी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शनिवार को चंदौली में छह जिलों (चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस व औरैया) के एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास व भूमि पूजन किया। सीएम योगी ने मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिह्न प्रदान किया और सभी न्यायमूर्तियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि न्यायपालिका भी उतनी ही सशक्त हो। आम आदमी को जितनी सहजता-सरलता से न्याय प्राप्त हो, उतना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। यूपी सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कोई

भी कार्य आते हैं तो उसे पूरा होने में देर नहीं लगती। हमारा मानना है कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो न्यायिक सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और यूपी इसे लेकर बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यहां न्यायपालिका के इतिहास के नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पुरानी बातों का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अपनी एक यात्रा के दौरान उल्लेख किया था कि न्याय सहजता के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए, जो इंटीग्रेटेड (एक छत के नीचे) हों। मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से यूपी के छह जनपदों (चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस व औरैया) में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगले कुछ महीने में चार अन्य जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। भारत के न्यायिक इतिहास में यह पृष्ठ नए स्वर्ण अक्षर के रूप में जुड़ेगा। यूपी में इसकी शुरुआत मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से हो रही है।

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम सुधार किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। पीएम से हमें भी प्रेरणा मिली। प्रयागराज के एक कार्यक्रम में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इस पर हम लोगों ने यूपी के अंदर कार्य प्रारंभ किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बिंदल जी ने सकारात्मक सहयोग किया और यूपी सरकार ने एक साथ 10 जनपदों में (जहां स्वयं के जनपद न्यायालय नहीं थे) इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए स्वीकृति दी।

सीएम ने कहा कि पहले चरण में चंदौली समेत छह जनपदों के लिए धनराशि अवमुक्त हो गई है। डिजाइन अप्रूव होने के साथ ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। एलएंडटी जैसी विश्व विख्यात संस्थाओं के द्वारा अब निर्माण कार्य होगा। यहां एक ही छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स, अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास, कैंटीन, पार्किंग, खेल आदि की सुविधाएं रहेंगी। सीएम ने कहा कि न्याय के लिए जूझने वाले अधिवक्ता के चैंबर में जब वादकारी जाता था तो उसे सूर्य के दर्शन होते थे, लेकिन अब टूटे चैंबर्स नहीं, बल्कि हाईराइज बिल्डिंग में चैंबर की व्यवस्था होगी।

सीएम योगी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर जनपद में ऐसे कोर्ट कॉम्प्लेक्स हों। अभी छह जनपदों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, आपको सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। चंदौली के जनप्रतिनिधि व अधिवक्ता लगातार आंदोलन करते थे, मैंने बार एसोसिएशन को लखनऊ बुलाकर कहा कि यह स्वीकृत हो गया है। आप न्यायिक कार्य में योगदान दीजिए। अब उच्च न्यायालय के साथ मिलकर यह कार्य शीघ्र आगे बढ़ेगा।

एनआरएलएम के तहत 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और 1 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तैयार किए गए विस्तृत एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इस कार्ययोजना के तहत प्रदेश की 3 करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने तथा 1 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।उप मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि नए स्वयं सहायता समूहों के गठन, नए सदस्यों को जोड़ने और लखपति दीदी बनाने से संबंधित जनपदवार लक्ष्य आवंटन की समस्त सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वाकांक्षी योजना में धनराशि का समयबद्ध और शत-प्रतिशत सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने जानकारी दी कि अब तक प्रदेश में 9,06,225 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 99,39,191 परिवारों की महिलाओं को योजना से आच्छादित किया जा चुका है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष पात्र परिवारों को भी विशेष अभियान के माध्यम से जोड़ना आवश्यक बताया गया है।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार जीरो पावर्टी अभियान के तहत ऐसे 6,67,075 परिवार चिन्हित किए गए हैं जो अभी तक समूहों से नहीं जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी और अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 2.90 करोड़ राशन कार्डधारक परिवारों में से अवशेष 2.10 करोड़ परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 19,39,967 अवशेष लाभार्थी, 17,38,489 अवशेष विधवा पेंशन लाभार्थी तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना से आच्छादित परिवारों में से छूटे हुए पात्र निर्धन परिवारों की महिलाओं को विशेष अभियान और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं, ऋण, प्रशिक्षण, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंडल, जनपद और विकास खंड स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति मासिक तथा विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक 15 दिवस पर बैठक कर प्रगति की समीक्षा करेगी। इन बैठकों में समूह गठन, नए सदस्यों का जुड़ाव, बैंक खाते खोलने और लोकोस सखी ऐप पर एमआईएस प्रविष्टि की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि मुख्य विकास अधिकारी स्वहस्ताक्षर से कार्यक्रम की प्रगति आख्या नियमित रूप से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्यालय को भेजेंगे। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्र गृहस्थी और अन्त्योदय योजना के लाभार्थी परिवारों की महिलाओं को शत-प्रतिशत स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित करते हुए विकास खंडवार लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर समीक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम लखनऊ द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में योजना की प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रदेश में समावेशी विकास तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगा।

छह जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास, चंदौली से न्यायिक इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में चंदौली में छह जिलों—चंदौली, महोबा, अमेठी,लखनऊ(आरएनएस) शामली, हाथरस और औरैया—के एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिह्न प्रदान कर सभी न्यायमूर्तियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टि से ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए न्यायपालिका का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है और आम आदमी को सरल व सहज न्याय मिले, इसके

लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका अहम है।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी कार्य में देरी नहीं करती। सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना अनिवार्य है और इस दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी की दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायपालिका के इतिहास में एक नए अध्याय का सृजन हो रहा है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पूर्व विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि न्याय को नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की अवधारणा अत्यंत उपयोगी है और उसी प्रेरणा से प्रदेश के छह जनपदों में यह सुविधा शुरू की जा रही है। आने वाले महीनों में चार अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार के न्यायालय परिसर स्थापित किए जाएंगे, जो भारतीय न्यायिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की दिशा में व्यापक सुधार किए गए। इसी सोच से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की योजना पर कार्य शुरू हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सकारात्मक सहयोग से प्रदेश के उन दस जनपदों में, जहां स्वयं के जनपद न्यायालय नहीं थे, एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्वीकृति दी गई।मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में चंदौली समेत छह जनपदों के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। डिजाइन स्वीकृत होने के साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब एलएंडटी जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य कराया जाएगा। इन परिसरों में एक ही छत के नीचे न्यायालय, अधिवक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास, कैंटीन, पार्किंग और खेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि पहले अधिवक्ताओं के जर्जर चैंबरों में वादकारियों को असुविधा होती थी, लेकिन अब हाईराइज भवनों में आधुनिक चैंबर की व्यवस्था होगी, जिससे कार्य संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन छह जनपदों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है और भविष्य में इसे हर जिले तक विस्तार दिया जाएगा। चंदौली के जनप्रतिनिधियों और अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इसे स्वीकृति देकर न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा देने का कार्य किया हैशिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्र, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा वरिष्ठ न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी सहित कई गणमान्य न्यायमूर्ति उपस्थित रहे।

दावोस में उत्तर प्रदेश की वैश्विक दस्तक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में निवेश अवसरों को करेगा सशक्त प्रस्तुतीकरण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी प्रभावी और सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल प्रतिभाग करेगा। इस वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उद्योग जगत के प्रमुख नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित करते हुए राज्य में उपलब्ध रणनीतिक निवेश अवसरों को आगे बढ़ाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नई औद्योगिक नीतियों, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे के चलते प्रदेश देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में शामिल हुआ है। इसी क्रम में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भागीदारी राज्य की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस पूरी सहभागिता का समन्वय इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है।वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य सुरेश कुमार खन्ना करेंगे। उनके साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव अमित सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव तथा इन्वेस्ट यूपी एवं यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद और ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव एवं यूपीनेडा के निदेशक इंदरजीत सिंह भी शामिल रहेंगे। यह प्रतिनिधिमंडल वैश्विक मंच पर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और उभरते निवेश क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेगा।दावोस में उत्तर प्रदेश का विशेष फोकस राज्य को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने पर रहेगा। इसके साथ ही निवेश-केंद्रित प्रस्तुतियों, मल्टीमीडिया शोकेस और सुनियोजित द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, पर्यटन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष रखा जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुदृढ़ करने, पारदर्शी प्रशासन तथा समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन के संदेश के साथ प्रदेश की प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित किया जाएगा।उत्तर प्रदेश का विशाल उपभोक्ता बाजार, मजबूत सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, आधुनिक औद्योगिक क्लस्टर, निवेशकों के अनुकूल नीतियां और सिंगल विंडो सिस्टम आधारित इकोसिस्टम वैश्विक कंपनियों के लिए इसे एक आकर्षक निवेश केंद्र बना रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस 2026 में प्रदेश की सहभागिता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश उच्च गुणवत्ता वाले निवेश को आकर्षित करने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को गहरा करने और भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार वैश्विक सहभागिता और रणनीतिक संवाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश दीर्घकालिक, समावेशी और सतत विकास के अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।

डायमंड डेरी कॉलोनी में प्रभारी मंत्री का दोबारा औचक निरीक्षण, सफाई में सुधार पर संतोष, ओपन जिम निर्माण के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखनऊ जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डायमंड डेरी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था और पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति परखने के लिए पुनः अचानक निरीक्षण किया। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने जोन एक के विभिन्न वार्डों में प्रातः सात बजे औचक निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया था, जहां खामियां और लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों व संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई गई थी।शुक्रवार के निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए प्रभारी मंत्री आज फिर डायमंड डेरी कॉलोनी पहुंचे और जमीनी हकीकत को परखा। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सफाई कार्य लगातार जारी है।

तय हुई जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश में वन विभाग को मिली बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कुछ वर्षों से वन विभाग ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बंदर नगर निगम को पकड़ना है जबकि शासन की ओर से ऐसा कोई शासनादेश भी जारी नहीं हुआ था। अब शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। बंदर पकड़ना वन विभाग की ही जिम्मेदारी है। -डॉ. अरविंद राव, अपर नगर आयुक्त

लखनऊ। लंबे समय से बंदरों को पकड़ने को लेकर नगर निगम और वन विभाग के बीच चल रही खींचतान पर शनिवार को विराम लग गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बंदर पकड़ने और उनके प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग को सौंप दी गई है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बैठक में स्पष्ट किया गया कि बंदर वन्यजीव की श्रेणी में आते हैं और उनके व्यवहार, प्रबंधन व पुनर्वास से जुड़ी विशेषज्ञता वन विभाग के पास उपलब्ध है। इसी आधार पर यह जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंपी गई है। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक माह के भीतर समेकित कार्ययोजना तैयार करे। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों का सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल, बंदरों का आतंक केवल राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे प्रदेश में गंभीर रूप ले चुकी है। आए दिन बंदरों के हमले और काटने की शिकायतें सामने आ रही थीं, लेकिन जिम्मेदारी तय न होने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। नगर निगम और वन विभाग के बीच इसे लेकर कई बार पत्राचार हुआ और मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा। इसके बाद शासन स्तर पर निर्णय लेते हुए स्थिति स्पष्ट की गई। बंदर पकड़ने को लेकर नगर निगम और वन विभाग के बीच करीब पांच वर्षों से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। दोनों विभाग जिम्मेदारी लेने से बचते रहे, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को जारी शासनादेश को लाखों लोगों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है। बंदरों के काटने के मामलों में रैबीज का खतरा बना रहता है। अकेले लखनऊ में प्रतिदिन 10 से 12 मामले सामने आते हैं। प्रदेशभर में बीते एक वर्ष में ऐसे 10800 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अनुमान के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 55 हजार से अधिक लोग बंदरों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, हालांकि घायलों की आधिकारिक संख्या किसी भी विभाग के पास संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है। जारी आदेश के अनुसार, नगर निगम की जिम्मेदारी उन पशु-पक्षियों तक सीमित है।

अनंतराम जायसवाल की 11वीं पुण्यतिथि पर सपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा, पार्टी नेताओं ने किया नमन

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व सांसद अनंतराम जायसवाल की 11वीं पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया।समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से अनंतराम जायसवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि अनंतराम जायसवाल समाजवादी आंदोलन के सच्चे सिपाही थे, जिन्होंने जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका सादगीपूर्ण जीवन और संगठन के प्रति समर्पण आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है।श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, अनंतराम जायसवाल के पौत्र दर्श जायसवाल, पूर्व सांसद अरविन्द सिंह, समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल, समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा, समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने अनंतराम जायसवाल के राजनीतिक जीवन, संगठनात्मक क्षमता और समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।इस अवसर पर के.के. श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह, राधेश्याम सिंह, दारा सिंह, डॉ. आलोक यादव, प्रोफेसर श्रवण गुप्ता, इंजीनियर अरविंद यादव, संतोष कृष्ण त्रिपाठी, मुन्नी लाल यादव, राम प्रताप गौतम, रीता राव, सुनील तंतुआ, हाजी इशहाक सिद्दीकी, विजय साहू मून, विवेक, मोहम्मद साहिल, विकास निषाद, गणेश निषाद, अखिलेश पटेल, बालमुकुंद धूरिया, जावेद अली, शाश्वत प्रजापति, अनुज सिंह थरिया, श्याम नारायण, प्रवीन यादव, डॉ. अंशुकी यादव, हरिकेश, मालती, कन्हाई लाल, अनुज निषाद, अजय यादव, पंकज, सौरभ कुमार मौर्य, किरन यादव, अनिल भारती सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम में निवेश आकर्षित करने स्विट्जरलैंड जाएगा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम में भाग लेने स्विट्जरलैंड जाएगा। प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना करेंगे।वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन 19 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दाओस शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल देश-विदेश के निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेगा। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, पर्यटन, सौर ऊर्जा सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों को लेकर संवाद किया जाएगा, ताकि प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिल सके।

विधान भवन में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को लेकर लखनऊ में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था, 1683 पुलिसकर्मियों की तैनाती

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। 18 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 86वें सम्मेलन (AIPOC) एवं विधायी निकायों के सचिवों के 62वें सम्मेलन को लेकर पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण आयोजन विधान भवन में संपन्न होगा, जिसमें देशभर से पीठासीन अधिकारी, विधायी निकायों के सचिव और अनेक अति विशिष्ट अतिथि सपरिवार प्रतिभाग करेंगे।सम्मेलन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा एवं राज्यसभा के महासचिव सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति प्रस्तावित है। प्रतिभागियों का आगमन 18 जनवरी की सुबह से प्रारंभ होगा, जबकि मुख्य सम्मेलन कार्यक्रम का समापन 21 जनवरी को होगा। इसके बाद 22 जनवरी को धार्मिक स्थलों का भ्रमण तथा 23 जनवरी को लखनऊ से प्रस्थान प्रस्तावित है। सभी अतिथियों का प्रवास पूर्व निर्धारित होटलों और गेस्ट हाउसों में रहेगा, जहां से वे तय कार्यक्रम के अनुसार आवागमन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन को देखते हुए लखनऊ में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सघन पुलिस व्यवस्था लागू की गई है। विधान भवन, कार्यक्रम स्थल, अतिथियों के प्रवास स्थल और आवागमन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में पर्याप्त पुलिस बल, पीएसी और यातायात पुलिस की तैनाती की गई है। एंटी-सबोटाज चेकिंग, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और एंटी-माइन टीमों के माध्यम से लगातार जांच की जा रही है, जबकि सीसीटीवी कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थल और संवेदनशील क्षेत्रों को विभिन्न जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है। फील्ड डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत कुल 1683 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इनमें पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षक, उप-निरीक्षक, महिला पुलिसकर्मी, मुख्य आरक्षी, आरक्षी और होमगार्ड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पीएसी की पांच कंपनियां, एटीएस की टीमें, डीएफएमडी, बीडीडीएस, एएस चेक टीम, फायर सर्विस और खुफिया इकाइयों की भी तैनाती की गई है।सम्मेलन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी पुलिस, प्रशासनिक और सुरक्षा इकाइयों की संयुक्त ब्रीफिंग कर ड्यूटी पॉइंट, रूट प्लानिंग और वीवीआईपी प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए रूट रिहर्सल, मेडिकल रिस्पांस और भीड़ प्रबंधन से जुड़ी मॉक ड्रिल भी कराई गई है।यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। आयोजन स्थल तक जाने वाले मार्गों पर आवश्यकता के अनुसार डायवर्जन व्यवस्था की गई है और आमजन की सुविधा के लिए अलग से यातायात परामर्श जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सीसीटीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से चौबीस घंटे निगरानी रखी जा रही है। कार्यक्रम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस चौकियां, पीआरवी यूनिट और फायर स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं।

पीड़ितों का शास्त्र न बन जाए उमर-शरजील की हिरासत

छह साल पहले राजधानी दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी हिस्से के जाफराबाद और मौजपुर में हुए दंगों पर राजनीति थम नहीं रही है। राजनीति तब भी खूब हुई, जब 23 फरवरी 26 फरवरी 2020 के बीच हुए दंगों का घाव बिल्कुल हरा था। इस बार इन दंगों पर राजनीति की वजह पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आया एक आदेश है, जिसमें इन दंगों के पांच आरोपियों गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी गई है। इस आदेश को लेकर राजनीति ही नहीं हो रही, प्रकारांतर से देश की सबसे बड़ी अदालत भी निशाने पर है। सर्वोच्च अदालत ने इन दंगों के आरोपी शरजील इमाम उमर खालिद को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर इन दोनों आरोपियों के पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई। मनमोहन सिंह की सत्ता और कांग्रेस के आंख के तारे रहे जेएनयू के पूर्व छात्र रहे एक बड़े पत्रकार ने इन दोनों आरोपियों को देश का प्रखर बुद्धिजीवी बताते हुए उन्हें जमानत ना दिए जाने पर आश्चर्य जताया।

वामपंथी वैचारिकी की एक खासियत है। वह अपने पक्ष में अकादमिक तर्क गढ़ने में माहिर रही है। अपने लिहाज के तथ्यों को चुनकर उसके हिसाब से वह तर्क गढ़ने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही अपनी वैचारिकी के लोगों को पीड़ित दिखाने में वह हमेशा आगे रहती रही है। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में वामपंथी वैचारिकी उसी तरह से उमड़ पड़ी है। वह दोनों के बारे में यह राय बनाने की भरपूर और प्रभावी कोशिश कर रही है कि दोनों दंगाई नहीं, दंगे के शातिर षड्यंत्रकारी नहीं, बल्कि वे प्रखर बुद्धिजीवी हैं। वामपंथी वैचारिकी यह साबित करने की भी कोशिश कर रही है कि दोनों चूंकि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय से हैं, और चूंकि केंद्र में हिंदुत्ववादी सत्ता है। इसलिए अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों को दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात यह विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्ववादी सत्ता के इशारे पर अदालत मुस्लिम समुदाय के निर्दोष बुद्धिजीवियों को बलि का बकरा बना रही है। यह विमर्श खड़ा करके वामपंथी वैचारिकी और उसकी बुद्धिजीवी जमात दरअसल दंगाईयों को पीड़ित के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प यह है कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को नकारने के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं बाकी पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के आदेश को जबरदस्ती नेपथ्य में धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो लोगों को जमानत ना मिलने को, पांच लोगों को जमानत मिलने की प्रक्रिया के सामने पक्षपाती दिखाया जा रहा है। पांच आरोपियों को मिली जमानत को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा करके सर्वोच्च अदालत ने कोई एहसान नहीं किया है। वामपंथी वैचारिकी के इस विमर्श का पूरा मकसद यह भुलाना है कि 2020 के दिल्ली दंगे हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं थे। इस विमर्श का लक्ष्य यह भी भुलाना है कि इन दंगों में अधिसंख्य हिंदू समुदाय के लोग मारे गए थे। इस विमर्श का यह भी मकसद है कि इन दंगों के दौरान आईबी के मासूम अधिकारी अंकित शर्मा की हुई हत्या को सामान्य अपराध दिखाने की कोशिश हो रही है। इन दंगों में आधिकारिक रूप से 53 लोग मारे गए थे। दंगा खत्म होने के बाद कई लाशें नाले में बहती मिलीं। जिस तरह उस दौरान दंगे के एक आरोपी आम आदमी पार्टी के तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन के घर पत्थर, हथियार और बड़ी-सी गुलेल मिली, उससे तो यही साबित होता है कि दिल्ली के ये दंगे हिंदू समाज को सबक सिखाने की मुस्लिम समाज के कुछ दंगाइयों की कोशिश थी। इन दंगों की टाइमिंग को भी भुलाना आसान नहीं है। जब ये दंगे हुए थे, उसके कुछ ही दिन बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप का भारत दौरा हुआ था। इन दंगों के जरिए कोशिश यह भी की गई थी कि दंगा के षड्यंत्रकारियों का मकसद ट्रंप की भारत यात्रा को निरस्त कराना, भारतीय राज व्यवस्था को बदनाम करना और इसके जरिए भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाना था। इसमें किंचित वे कामयाब भी हुए। शरजील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में उठती आवाजों का प्रतिकार भी जरूरी है। इन आवाजों की पोल खोलना भी जरूरी है। राष्ट्रवादी धारा के प्रबुद्धजन वामपंथी विमर्श के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जिस तरह कभी वामपंथी वैचारिकी के अगुआओं को देश की मौजूदा व्यवस्था में राजकीय तवज्जो मिल रहा है, उससे प्रखर राष्ट्रवादी वैचारिकी किंचित परेशान भी है और दुखी भी। इसलिए जैसा इस वामपंथी विमर्श का प्रतिकार होना चाहिए, उस स्तर का प्रतिकार नहीं हो पा रहा है। यह तो भला हो कि हिंदुत्ववादी मानस इन दिनों बेहद सचेत हो चुका है। निश्चित तौर पर इसकी वजह मुस्लिम तुष्टिकरण की हकीकत का सामने आना तो है ही, केंद्रीय सत्ता में मोदी की अगुआई में हिंदुत्वादी ताकतों का प्रभावी बनना भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में एक सफल राजनीतिक सिस्टम बनाया है

अजय दीक्षित

2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजग का महत्व मालूम हुआ कि भारत में सबसे अधिक राजनीतिक समन्वय की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में एक ऐसा सफल राजनीतिक सिस्टम बनाया है कि जो उनमें शामिल दलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आदर बढ़ा है साथ साथ में उनकी विश्वसनीयता भी बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सीटों के बंटवारे से पहले लोकजनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा नरेंद्र मोदी है न सब सुलझा देगे।यही बात मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कही ।2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में जेडीयू 115 सीट पर लड़ी थी 2025 में 101 पर लड़कर 85 पर जीत गई ।यह सब मैं इस लिए लिख रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई तो ऐसी बात होगी जो उन्हें लगातार साथी दलों में स्वीकार्य बनाए है।यह गुण उन्होंने अटल बिहारी वाजपेई से सीखा है।स्व अटल बिहारी वाजपेई ने ही राजग की स्थापना की थी।

जब 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजग का महत्व मालूम हुआ कि भारत में सबसे अधिक राजनीतिक समन्वय की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तमिलनाडु में एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में जेडीयू, लोकजनशक्ति पार्टी, जीतनराम मांझी की हम ,असम में एजीपी, और पूर्वोत्तर में कई क्षेत्रीय दल, महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना,है। बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में अजीत पवार, शिंदे, तमिलनाडु में पनीरसेलम, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, उनके सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया थे तब उनकी सभी पार्टियों में स्वीकारता नहीं थी क्योंकि वह गुजरात से दिल्ली आए थे और उससे पहले गुजरात के 2002 से मुख्यमंत्री थे । नीतीश कुमार भी उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री थे ।जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो उन्हें यह अटपटा लगा तो वे मोदी को राजग नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सके और अलग होकर चुनाव लड़े लेकिन बिहार में लोकसभा 2014 में उनकी पार्टी मात्र दो सीट ही जीत सकी। समय बीता तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर पुनः एनडीए में शामिल हो कर सरकार बना ली।यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जीत थी समन्वय की । इसके बाद 2019 में नीतीश कुमार ने मोदी नेता मान लिया था और मोदी भी नीतीश कुमार की कोई बात नहीं टालते यहां तक कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 47 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 77 तब भी मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जबकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है बस यही से नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक गॉड फादर मान लिया।2024 में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था लेकिन ह्रष्ट्र में नीतीश कुमार ने मोदी को मदद की और उन्हें हाथ फैलाने नहीं दिया।इसका पुरस्कार फिर मोदी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में दिया है और नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अटलजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं अभी हाल में लोकसभा सत्र समाप्ति पर प्रियंका गांधी को खासी तब्बजो दी।इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे को साद रखा है।

यहां तक कि शरद पवार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है मगर कई निर्णयों में सरकार के साथ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उन्होंने ठौर बैठा दिया है क्योंकि 2020 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 117 सीट मिली और शिवसेना को 57 मिली थी फिर भी संजय राउत शिवसेना के लिए मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे जबकि तय यह हुआ था कि जिसकी सीट अधिक आएगी वह मुख्यमंत्री का हकदार होगा। इतना ही नहीं शिवसेना ने कांग्रेस, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली।तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह धोखा लगा ।दो वर्ष बाद ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना टूट गई और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और शिवसेना 2025 का चुनाव में बुरी तरह हार गई। आज एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद बने हुए हैं। इसी तरह तमिलनाडु में एआईडीएमके नेता पानीरसेवम उनकी पसंद बने हुए हैं।अबकी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना डीएमके नेता और मुख्यमंत्री रूद्य स्टालिन की ओर है भारतीय जनता पार्टी यहां पर 17 फीसदी वोट हासिल कर चुकी है। एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे।

आंध्र प्रदेश में 2014 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों साथ साथ हुए थे तब टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने लेकिन उन्होंने कुछ मुद्दों तथा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ता से मना कर दिया क्यूंकि ये भारत के संविधान के खिलाफ था ।2019 के विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जीती तब जाकर चंद्रबाबू नायडू को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंगा लेना ठीक नहीं है 2024 में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर लड़े तो जीत हासिल हुई और आज मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्रो में नवीन पटनायक, गुलामनबी आजाद,शरद पवार, नीतीश कुमार, शंकर सिंह बघेला,शामिल है। समाजवादी पार्टी के नेता स्व मुलायम सिंह से उनकी अच्छी मित्रता थी जिसे ने अखिलेश यादव के साथ भी राजनीतिक मामलों को छोड़कर निभाते है।

टिप्पणी

नियम-कानून की कोई परवाह नहीं

नेशनल हेराल्ड मामले में वैध एफआईआर ही मौजूद नहीं है। क्या ईडी के अधिकारियों को कानून की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो वे नियम- कानून की कोई परवाह नहीं करते?

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को राहत मिली, मीडिया की सुर्खियों में इसी पहलू को अहमियत दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसका यह सिर्फ एक पक्ष है। लेकिन यह मूल बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं को राहत इसलिए मिली, क्योंकि जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संज्ञान इसलिए नहीं लिया, क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले की एफआईआर ही वैध ढंग से दर्ज नहीं हुई है। हुआ यह कि एक व्यक्ति (भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी) ने निजी तौर पर एफआरआर दर्ज कराई। उसमें कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए।

ईडी ने उसी मामले में जारी समन के आधार पर केस अपने हाथ में लेकर में जांच शुरू कर दी। यानी उसने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। जज विशाल गोगने ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून की संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी निजी एफआईआर के आधार पर चार्जशीट तैयार नहीं कर सकती। जज का यही वो निष्कर्ष है, जो ईडी की कार्यशैली को बेनकाब कहता है। सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को कानूनी धाराओं की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो अपने सियासी आकाओं के इशारे पर वे नियम- कानून की कोई परवाह नहीं करते?

सत्ताधारी भाजपा और उसके समर्थक नेटवर्क ने वर्षों से नेशनल हेराल्ड मामले को गांधी परिवार के कथित भ्रष्टाचार की मिसाल बता कर प्रचारित किया है। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ हुई। मगर अब सामने आया है कि यह सब उस मामले में हुआ, जिसमें एफआईआर ही वैध नहीं थी। सामान्य स्थितियों में कायदे का इस रूप में उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती, ताकि भविष्य में अधिकार के ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी उम्मीद करना बेमतलब है। अभी तो संभावना यही है कि ऊपरी अदालत में अपील की आड़ में सारा मामला पृष्ठभूमि में डाल दिया जाएगा।

ब्लॉग

पंचायत उन्नति सूचकांक: ग्रामीण परिवर्तन के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने को मजबूत करना

सुशील कुमार लोहानी

भारत के गांवों में एक शांत लेकिन असरदार बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र की एक पंचायत में महिला-अनुकूल पंचायत विषय में कम अंक आने पर सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं, वहीं गुजरात के एक गांव में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में कमजोर प्रदर्शन के बाद तेजी से स्वच्छता अभियान शुरू किए गए।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) अब यह तय करने लगा है कि जमीनी स्तर पर विकास की योजना कैसे बने और उसे कैसे लागू किया जाए। कई पंचायतों में पीएआई के जरिए सामने आई कमियां जैसे संस्थागत प्रसव की कम संख्या, खराब कचरा प्रबंधन या पानी की कमी के आधार पर सीधे लक्षित कदम उठाए गए हैं।

ये शुरुआती उदाहरण एक सरल लेकिन मजबूत सच्चाई दिखाते हैं-जब पंचायतें अपनी ताकत और कमज़ोरियों को साफ़-साफ़ देख पाती हैं, तो वे ज़्यादा तेज़ी से और सही तरीके से काम करती हैं। कई दशकों तक भारत में ग्रामीण विकास ज़्यादातर हाथ से बनी रिपोर्टों, व्यक्तिगत धारणाओं और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहा। आज पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) ग्रामीण प्रशासन के केंद्र में एक नया मॉडल लेकर आया है, जो पारदर्शी है, आंकड़ों पर आधारित है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है।

पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) भारत का पहला देशव्यापी ढांचा है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों की प्रगति को वस्तुनिष्ठ संकेतकों के आधार पर मापा जाता है। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, शासन, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा, पर्यावरणीय स्थिरता आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह मूल्यांकन 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से निकले स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के नौ विषयों के अंतर्गत किया जाता है।

तर्कसंगत रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की प्राप्ति के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यवाही आवश्यक है, जहां पंचायतें अहम भूमिका निभा सकती हैं। इस संदर्भ में, पीएआई ग्रामीण क्षेत्रों में एलएसडीजी और अंततः एसडीजी की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए एक साक्ष्य-आधारित व्यवस्था प्रदान करता है।

पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) की गणना एक मजबूत और बहु-चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें नौ विषयों के अंतर्गत 435 अलग-अलग स्थानीय संकेतकों का उपयोग होता है। पंचायती राज मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से परामर्श कर संकेतकों का ढांचा तैयार करता है, जबकि वास्तविक आंकड़े ग्राम पंचायतों और संबंधित विभागों द्वारा एक साझा पोर्टल श्चड्डद्व.द्दश1.द्वठ्ठ पर ग्राम पंचायत स्तर पर दर्ज किए जाते हैं।

इन आंकड़ों का सत्यापन कई प्रशासनिक स्तरों पर किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा जांच भी शामिल है। प्रत्येक विषय का स्कोर इन संकेतकों के आधार पर 0 से 100 के पैमाने पर तय होता है और इन्हीं से कुल पीएआई स्कोर (0-100) बनता है। इसी कुल स्कोर के आधार पर पंचायतों को तुलना के लिए पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किए गए पहले सर्वेक्षण से कई रोचक तथ्य सामने आए। सत्यापित आंकड़े जमा करने वाली 2.16 लाख पंचायतों में से कोई भी पंचायत अचीवर (90 से अधिक अंक) की श्रेणी में नहीं आई। केवल 0.3 प्रतिशत पंचायतें फ्रंट रनर (75-89.99 अंक) रहीं और 35.8 प्रतिशत पंचायतें परफॉर्मर (60-74.99 अंक) की श्रेणी में थी।

सबसे अधिक, यानी 61.2 प्रतिशत पंचायतें आकांक्षी (40-59.99 अंक) श्रेणी में रहीं, जबकि 2.7 प्रतिशत पंचायतें शुरुआती (40 से कम अंक) श्रेणी में पाई गई। गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य सबसे अधिक उच्च प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के साथ शीर्ष पर रहे।

जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करने में इसकी बड़ी क्षमता को देखते हुए, राज्य सरकारें पीएआई अंकों को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों तक पहुंचा रही हैं। पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए पंचायतों ने अपने कार्यालयों के बाहर पीएआई स्कोरकार्ड लगाना भी शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडे में भी पीएआई अंकों पर चर्चा को शामिल किया जा रहा है।

पीएआई की असली ताकत इसके व्यावहारिक उपयोग में है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि गुजरात जैसे राज्य पीएआई अंकों का उपयोग कमजोर ग्राम पंचायतों को विशेष अनुदान देने में कर रहे हैं, ताकि महत्वपूर्ण कमियों को पूरा किया जा सके। सिक्किम ने अपने छठे राज्य वित्त आयोग के तहत प्रदर्शन अनुदान देने के लिए पीएआई स्कोर को एक मानदंड के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है।

कई राज्यों में पीएआई साक्ष्य-आधारित योजना बनाने का एक अहम साधन बन गया है, जिससे पंचायतों को अपने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीडीडीपी) में प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद मिल रही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में उच्च अंक पाने वाली ग्राम पंचायतों को पंचायत लर्निंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि झारखंड, बिहार, केरल, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य इन पंचायतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के प्रतिनिधियों के लिए विशेष अध्ययन और अनुभव भ्रमण आयोजित कर रहे हैं।

अब कई राज्य पीएआई के प्रदर्शन को सम्मान और पुरस्कारों से भी जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योजना के तहत बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं; सिक्किम और मध्य प्रदेश में वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं, जबकि पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में उच्च अंक प्राप्त पंचायतों को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, पीएआई अंकों को अब संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भी तेजी से शामिल किया जा रहा है।

पीएआई ने जटिल सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संकेतकों को आसान और समझने योग्य विषयों में बदल दिया है, जिससे लक्षित योजना बनाने और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। डैशबोर्ड, स्कोरकार्ड और डिजिटल उपकरण पंचायत स्तर पर साक्ष्य-आधारित शासन को मजबूत करते हैं।

हालांकि, पीएआई अभी नया है। इसकी पहली आधारभूत रिपोर्ट 2022-23 की है, इसलिए ऐसे लंबे समय के अध्ययन अभी कम हैं जो सीधे और मापने योग्य सुधार दिखा सकें। तकनीकी क्षमता में असमानता, आंकड़ों की सही समझ की कमी और रिपोर्टिंग प्रणालियों में एकरूपता न होने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में डेटा की गुणवत्ता भी अलग-अलग है। विभागों और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के बीच समन्वय बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह सुदृढ़ नहीं है।

ये समस्याएं नहीं, बल्कि अवसर हैं। इन्हीं अनुभवों से सीख लेते हुए मंत्रालय ने पीएआई 2.0 के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसमें विशिष्ट संकेतकों की संख्या 435 से घटाकर 119 कर दी गई है, अधिक प्रासंगिक और परिष्कृत संकेतकों को अपनाया गया है, और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया गया है, जिससे डेटा संग्रह आसान हो और उसकी गुणवत्ता भी सुधरे।

मंत्रालय से जारी स्पष्ट संचालन दिशानिर्देशों और सरल प्रक्रियाओं के कारण इसे लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया है। दूसरे चरण में 2.60 लाख से अधिक पंचायतों की भागीदारी हुई है, जबकि पहले चरण में यह संख्या 2.16 लाख थी, जो एक मजबूत दिशा को दर्शाता है। इसके साथ ही, चुने हुए जनप्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और संबंधित विभागों के कर्मचारियों में संकेतकों और डेटा बिंदुओं की समझ बढ़ाने के लिए एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

पीएआई की परिवर्तनकारी क्षमता को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह डेटा को लोकतांत्रिक बनाता है, जिससे नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाबदेही तय कर सकते हैं और लोकतांत्रिक शासन और मजबूत होता है। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

चूंकि विषयवार पीएआई अंक विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई संकेतकों पर आधारित होते हैं, इसलिए पीएआई अपनी संरचना में ही मंत्रालयों और विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, ताकि बेहतर विकास परिणाम हासिल किए जा सकें। पीएआई की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप है और इन लक्ष्यों का गांव स्तर पर नवाचारी स्थानीयकरण करता है। विकास को पीएआई अंकों के माध्यम से मापकर यह मॉडल वास्तव में एसडीजी के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारता है, जिससे यह एक अनूठा और संभावित रूप से वैश्विक सर्वोत्तम उदाहरण बनता है।

संक्षेप में, पंचायत उन्नति सूचकांक भारत में ग्रामीण शासन को नए सिरे से परिभाषित करने वाली एक ऐतिहासिक पहल है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, जो साक्ष्य-आधारित, सहभागितापूर्ण और विकेंद्रीकृत विकास योजना के माध्यम से भारत को वर्ष 2030 तक अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है।

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, जब भारत समान विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्रयासरत है, तब पीएआई पंचायतों को डेटा से विकास की ओर, और समझ से वास्तविक प्रभाव की ओर ले जाने वाला एक मार्गदर्शक प्रकाशस्तंभ बनकर खड़ा है।

(सुशील कुमार लोहानी एक आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं।)

मंदिर परिसर को रखें स्वच्छः तेजस के.

उपजिलाधिकारी ने कोटवाधाम मेले परिसर का किया निरीक्षण, दिए निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

सिरौलीगौसपुर बाराबंकी। कोटवाधाम मेले की तैयारियों का जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी तेजस के. व क्षेत्राधिकारी रामनगर गरिमा पंत ने निरीक्षण किया। निरीक्षण आगामी जन्म सप्तमी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए किया गया। उपजिलाधिकारी ने मेला परिसर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आगामी 25 जनवरी को होने वाले मेले की तैयारियां सुचारु रूप से चल रही हैं। उन्होंने आगामी सप्तमी मेले के लिए भी सभी संबंधित विभागों के समन्वय से बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।निरीक्षण के दौरान पिछली बार की कमियों पर भी चर्चा की

गई। उपजिलाधिकारी ने तालाब में गंदगी की समस्या को दूर करने और आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।उपजिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य सड़क पर पार्किंग बैरियर लगाने का निर्देश दिया, ताकि मेला परिसर में अतिरिक्त, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेरिकेडिंग की व्यवस्था करने को कहा गया, जिससे वे कतारबद्ध होकर आसानी से प्रसाद चढ़ा सकें। इस अवसर पर लेखपाल प्रदीप, साहब प्रसाद और अन्य कई लोग मौजूद रहे।

राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित हुआ व्यापारी संवाद कार्यक्रम

बाराबंकी। शनिवार को बाराबंकी सभागार में राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियों के मध्य जीएसटी-2.0 के सुधार, पंजीयन लाभ, रिटर्न दाखिला, समाधान योजना, टीडीएस, टीसीएस से सम्बंधित रिटर्न की व्यवस्था एवं व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना आदि विषयों से अवगत कराया गया तथा करदाताओं व उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा की गयी। इस अवसर पर उपायुक्त अंजू उपाध्याय द्वारा जीएसटी.-2. के सुधारों पर विचार व्यक्त करते हुए इससे होने वाले लाभ से अवगत कराया गया एवं सहायक आयुक्त ज्योत्स्ना सिंह द्वारा जीएसटी पंजीयन से होने वाले लाभ एवं सहायक आयुक्त शिव शंकर शुक्ला द्वारा ईंट भट्ठा व्यापारियों को वर्तमान में लागू 6 प्रतिशत 12 प्रतिशत समाधान योजना से अवगत कराया गया। विशेष रूप से इस अवसर पर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के लाभार्थी फर्म बालाजी कृषक सेवा केन्द्र के प्रोप्राइटर के भाई जितेन्द्र सिंह को अपर जिलाधिकारी द्वारा बीमा धनराशि रू0 10 लाख का चेक प्रदान किया गया।इस अवसर पर संजय पाठक, एडीएम निरंकार सिंह, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धकसौरभ मौर्य मौजूद रहे।

कर्नलगंज में अलाव जलवाने के नाम पर खानापूर्ति, रेलवे स्टेशन के पास नहीं जला अलाव

आर्यावर्त संवाददाता

गोण्डा। भीषण ठंड के बीच नगर पालिका परिषद कर्नलगंज की अलाव व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुल गई है। शासन व उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नगर क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थल रेलवे स्टेशन कर्नलगंज के पास शुक्रवार रात अलाव नहीं जलाया गया। रात लगभग 8:06 बजे की स्थिति ने प्रशासन के दावों को पूरी तरह झुंठला दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार स्टेशन परिसर व आसपास देर रात तक कोई अलाव नहीं जलाया गया, जिससे यात्रियों, राहगीरों व ठेला-पटरी लगाने वालों को ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग ठिठुरते रहे और जिम्मेदार अधिकारी नदारद दिखाई दिए। नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन नियमित अलाव जलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आई। सूत्रों का कहना है कि कई स्थानों पर अलाव केवल कागजों और रजिस्टरों में जल रहे हैं, जबकि मौके पर व्यवस्था पूरी तरह फेल है। अलाव जलवाने के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी सामने आ रही है। ठंड से राहत के लिए स्वीकृत बजट आखिर कहां खर्च हो रहा है, यह बड़ा सवाल बन गया है। नाम न छापने की शर्त पर नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर चुनिंदा जगहों पर ही अलाव जलवाया जाता है। कई स्थानों पर लकड़ी, पेट्रोल या केरोसिन जैसी आवश्यक सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे अलाव जलाना संभव नहीं हो पाता है। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ठंड के चलते किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता।

वैश्विक रैंकिंग के लिए वैज्ञानिकों का सामूहिक प्रयास जरूरी : डा . डी .के . सिंह

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। आचार्य नरेंद्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि महा विद्यालय में बोर्ड ऑफ फैकल्टी की बैठक आयोजित की गई। सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व शिक्षकों एवं छात्रों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा शिक्षा एवं शोध में उत्कृष्टता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता एवं चेयरमैन डा. डी. के. सिंह ने की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बोफा के चेयरमैन डॉ. डी. के. सिंह ने शिक्षण एवं शोध कार्यों में सतत सुधार हेतु सभी शिक्षकों से निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डा. सिंह ने कहा कि कुलपति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को निरंतर बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी शिक्षकों से आग्रह किया कि वे सामूहिक प्रयासों के माध्यम से शिक्षा एवं शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने तथा वैश्विक रैंकिंग प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं। सचिव बोर्ड ऑफ फैकल्टी डॉ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि लीव एनकैशमेंट, मेडिकल सुविधा, ग्रेच्युटी सहित महाविद्यालय से संबंधित शैक्षणिक, शोध एवं शिक्षकों के लाभ से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बोर्ड के सदस्य डा सीताराम मिश्रा ने बताया कि फैकल्टी की यह बैठक प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ से पूर्व आयोजित की जाती है जिससे कि शिक्षकों एवं छात्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। कहा कि इस प्रकार की बैठकों के माध्यम से शिक्षा एवं शोध से संबंधित नई जानकारियां दी जाती हैं। संगठन के कोषाध्यक्ष डॉ कमल रवि शर्मा ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। बैठक में प्रमुख रूप से निदेशक शोध डॉ शम्भू प्रसाद, पूर्व अधिष्ठाता डॉ प्रतिभा सिंह, डॉ सुशील कुमार सिंह, डॉ एन.ए. खान, डॉ रोबिन कुमार, डॉ पीयूष सिंह, चारू प्रिया, शिप्रा यादव सहित संकाय के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की हो बुवाई-- पी.एन. सिंह

गोण्डा। बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड कुंदरखी चीनी मिल में गन्ने की प्रजाति पहचान, बीज वितरण और उन्नतशील प्रजाति के गन्ने की बुवाई पर एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें उन्नतशील अगेती प्रजाति के गन्ने की बुवाई करने की सलाह दी गई। इस मौके पर सभी को गन्ने की अस्वीकृत, अवांछित और बेनामी प्रजातियों के बुवाई से बचने पर जोर दिया गया। इस दौरान गन्ने की पहचान हेतु उन्नतशील गन्ना किस्मों के नमूने भी प्रदर्शित किये गये।

इकाई प्रमुख पी.एन. सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के अत्यधिक आर्थिक लाभ दिलाने हेतु उन्हें केवल अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का वितरण कराया जाये और अगेती प्रजाति जैसे को० 0118, को० 15023, कोलख 14201, को० 98014, कोशा० 13235, कोलख 16202, कोशा० 18231 व कोजे० 85 आदि की ही बुवाई कराई जाए। वैज्ञानिक एस.पी. शुक्ला ने गन्ने की

मिल्कीपुर में बिजली संकट से मिलेगी राहत

आर्यावर्त संवाददाता

मिल्कीपुर-अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही विद्युत समस्याओं को लेकर विधायक चंद्रभानु पासवान ने प्रदेश के विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा से मुलाकात कर क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। विधायक द्वारा रखी गई समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विद्युत मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के लिए 54 नए ट्रांसफार्मरों की स्वीकृति प्रदान कर दी। इनमें 10 केवी और 16 केवी क्षमता के ट्रांसफार्मर शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार लगभग एक सप्ताह बाद क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। नए ट्रांसफार्मर लगने से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बार-बार होने वाली बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर फुंकने जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन ट्रांसफार्मरों से करीब एक हजार घरों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और किसानों को भी राहत मिलेगी। विधायक चंद्रभानु पासवान ने बताया कि इस समय बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में छात्रों को सुचारू रूप से बिजली मिलना बेहद जरूरी है, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विद्युत मंत्री से मिलकर क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने समस्या को गंभीरता से समझते हुए तत्काल ट्रांसफार्मरों की स्वीकृति दी, जिसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से उन्होंने आभार व्यक्त किया। विधायक ने कहा कि मिल्कीपुर क्षेत्र के कई गांवों और कस्बों में पुराने और कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों के कारण आए दिन फाल्ट और ओवरलोड की समस्या बनी रहती थी। नए ट्रांसफार्मर लगने से विद्युत आपूर्ति मजबूत होगी और गर्मी के मौसम में बढ़ने वाली मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा।

साकेत बुद्ध विहार को हटाने की नोटिसों के विरोध में हुई पंचायत

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) द्वारा ग्राम माझा बरहटा में स्थित साकेत बुद्ध विहार को हटाने के उद्देश्य से आवास विकास परिषद द्वारा जारी की जा रही नोटिसों के विरोध में तहसील सदर तिकुनिया पार्क पर पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने की तथा संचालन महिला जिला अध्यक्ष सविता मौर्य ने किया। जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि साकेत बुद्ध विहार वर्षों से क्षेत्र के नागरिकों एवं बुद्ध अनुयायियों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। यह ग्राम का एकमात्र बुद्ध विहार है और इसे हटाने का प्रयास संविधान के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। पंचायत के माध्यम से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि आवास विकास परिषद द्वारा जारी सभी नोटिस तत्काल निरस्त की जाएं तथा साकेत बुद्ध

विहार को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। पंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि धार्मिक स्थल के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई तो भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) विधिक एवं लोकतांत्रिक संघर्ष करेगी। पंचायत में प्रमुख रूप वरिष्ठ प्रदेश सचिव जगतपाल सिंह माया ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव मंजू रामप्यारी धरिया राम सुरेश संजय यादव दिनीराम रीमा राधाकेश कुमारी ममता देवी कंचन रामशिला तारावती गया देवी राजू पांडे मीडिया प्रभारी राजरानी मितादेवी रामवती राजकुमारी राजमणि यादव जिला उपाध्यक्ष संगठन मंत्री अर्जुन मौर्य सैकड़ो किसान उपस्थित रह।

'मैं या मेरा' नहीं 'हम और हमारा' के कुटुंबभाव से जुड़ता है हमारा समाज : डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी

आर्यावर्त संवाददाता

मिल्कीपुर-अयोध्या। समाज के वंचित , दुर्बल, उपेक्षित, निर्धन और अभावग्रस्त जीवन जीने वाले समाज के बांधवों की आत्मीयता से "मै और मेरा" की नहीं "हम और हमारा" के कुटुंब भाव से समाज को एकता और समभाव का जागरण समर्थ सेवाभावी बंधुओं के सक्रिय योगदान को सुनिश्चित कर सेवा और सहयोग किया जाना ही भारतीय संस्कृति का मूल भाव है। उक्त विचार अयोध्या महानगर के सह सेवा प्रमुख डॉ उपेन्द्र मणि त्रिपाठी ने पूरे लेदई तिवारी मवई कला मिल्कीपुर में स्व मनोकानिका तिवारी की पुण्यमृति में आयोजित कम्बल वितरण आयोजन में व्यक्त किए। सेवा निवृत पोस्ट मास्टर राम सहोदर तिवारी ने कहा उनके पिताजी और बड़े भाई की इच्छा सदैव अपने गांव को परिवार मानकर निर्बल परिवारजनों के सहयोग की रही और वे सदा हम सभी को प्रेरित

करते रहते थे, इसलिए समाज के लिए अपने पूर्वजों की प्रेरणा को सामर्थ्य अनुसार निभाने का संकल्प हमारा परिवार समाज का सहयोगी बनकर करता रहेगा। पूर्व डीएचओ डॉ राम विशाल तिवारी ने सभी को मिलकर गांव की छोटी मोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए सदैव एकमत होने और समर्थ बंधुओं की अगुवाई का आह्वान किया। आवश्यकता को पहचान कर उपयुक्त लाभार्थियों के लिए मवई कला से प्रधान प्रतिनिधि सुभाष तिवारी, बसवार खुर्द से पूर्व प्रधान जितेन्द्र दुबे, अछोरा से राम सहाय तिवारी एवं स्वयं मनोकानिका तिवारी द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर सूची बनाकर आमंत्रित परिवार को कम्बल उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर बृजेंद्र तिवारी, रामावती तिवारी, सचिन तिवारी, आयुष तिवारी, सत्यसर्वा तिवारी, सुरेश तिवारी, राम बहादुर तिवारी, शिव बहादुर तिवारी, रोहित तिवारी, देव प्रभाकर दुबे,प्रधान प्रतिनिधि सुभाष तिवारी , विष्णुदेव तिवारी, इंद्र देव तिवारी, अंकित तिवारी आदि उपस्थित रहे। कम्बल प्राप्त कर उपस्थित माताओं और वृद्धजनों ने सेवा सहयोग की भावना की बिना सराहना की। आयोजन में एडवोकेट धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी, इंजीनियर सौरभ त्रिपाठी, एवं वैभव त्रिपाठी का सहयोग रहा।

करियर फेयर में विद्यार्थियों को मिला सशक्त मार्गदर्शन

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। शहर के सनबीम विद्यालय में पहली बार करियर फेयर का सफल एवं भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों, उच्च शिक्षा की संभावनाओं तथा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण हेतु उचित एवं प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करना था।

इस अवसर पर अयोध्या मंडल की आरटीओ ऋतु सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया तथा उनके पालन के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने जीवन में शिक्षा के महत्व को बहुमूल्य बताते हुए उपलब्ध संसाधनों का सकारात्मक एवं सार्थक उपयोग कर लक्ष्य निर्धारण करने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आयोजकों को

बधाई देते हुए कहा कि ऐसा आयोजन छात्र छात्राओं को अपना करिअर चुनने में सहायक होगा । अभिभावकों को भी अपने बच्चों कि रुचि और योग्यतानुसार शिक्षा क्षेत्र चुनने चाहिए।

मुख्य अतिथि का स्वागत विद्यालय के निदेशक बृजेश यादव एवं निर्देशिका मेधा यादव द्वारा शॉल और मोमेंटो भेंट कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया, उप-प्रधानाचार्य पलक खन्ना एवं समन्वयक रितिका सिंह भी उपस्थित रहीं। सभी गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा और अधिक बढ़ गई। इस करियर फेयर में देश के 32 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों ने सहभागिता की। इनमें एडलीर्न कंसल्टेंट्स, एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ, एशियन बिज़नेस स्कूल, बेनेट विश्वविद्यालय, गीता विश्वविद्यालय, गणपत विश्वविद्यालय (गुजरात एवं गोवा), ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, आईआईएलएम विश्वविद्यालय, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, के. आर. मंगलम विश्वविद्यालय, यूईआई ग्लोबल, महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि रामायण विश्वविद्यालाय अयोध्या, महिंद्रा विश्वविद्यालय, मास्टर्स यूनियन, एमआईटी-डब्ल्यूपीयू विश्वविद्यालय, मोदी विश्वविद्यालय, पारुल विश्वविद्यालय, पर्ल अकादमी एवं यूपीईएस (यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़), पिल्लई विश्वविद्यालय, प्रथम, क्वांटम विश्वविद्यालय, ऋषिहुड विश्वविद्यालय, एसजीटी विश्वविद्यालय, सनबीम कॉलेज भगवानपुर, सनबीम कॉलेज वरुणा, संदीप विश्वविद्यालय, टेक्नो ग्रुप लखनऊ, टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सल एआई तथा गौटैम विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति, करियर संभावनाओं तथा भविष्य की दिशा से संबंधित विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। इस आयोजन में सनबीम विद्यालय अयोध्या एवं सनबीम विद्यालय गोंडा के साथ-साथ फैजाबाद पब्लिक स्कूल, कैनोसा, विनायक पब्लिक स्कूल, गुरु नानक अकादमी, अयोध्या अकादमी सहित अन्य विद्यालयों के छात्र-छात्राएँ अपने-अपने शिक्षकों के साथ उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से प्रत्यक्ष संवाद कर अपनी शैक्षणिक एवं करियर संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। कुल मिलाकर यह करियर फेयर विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी, मार्गदर्शक एवं प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार के करियर उन्मुख एवं शैक्षणिक आयोजनों को निरंतर आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की अयोध्या में इस प्रकार के करियर फेयर का यह पहला आयोजन था।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने करियप्पा मंडल के बूथों पर भरवाए नवमतदाताओं के फार्म

आर्यावर्त संवाददाता

अयोध्या। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में चार निर्धारित तिथियों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रथम दिन शनिवार को पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने करियप्पा मंडल के विभिन्न बूथों पर नवमतदाताओं से संवाद किया और पात्र युवाओं के फार्म संख्या-6 भरवाने की प्रक्रिया को गति दी। पूर्व सांसद को करियप्पा मंडल का प्रवासी नियुक्त किया गया है, जिसके तहत वे क्षेत्र में संगठनात्मक समन्वय और मतदाता जागरूकता का कार्य कर रहे हैं।

भ्रमण के दौरान पूर्व सांसद ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि बोगस मतदाताओं के नाम हटाने, मृतक मतदाताओं तथा स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के

नाम सूची से विलोपित कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाए। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मताधिकार दिलाना और मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करना है। युवा नवमतदाता लोकतंत्र की शक्ति हैं, उन्हें जोड़ना हमारी प्राथमिकता है, वहीं फर्जी और अपात्र नामों को हटाना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क कर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान मंडल रवि सोनकर, बुद्धिपाल प्रजापति सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

माघ मेला का सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आज ही उमड़ी भीड़

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। त्रिवेणी के तट पर लगे आस्था के महा समागम माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या के लिए माघ मेला प्रशासन ने कई नए कदम उठाए हैं। माघ मेला में पिछले दो स्नान पर्वों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस स्नान पर्व के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्नान घाटों का विस्तार , संगम नोज में भीड़ के प्रबंधन से लेकर हर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पर अमल शुरू हो गया है।

मौनी अमावस्या के एक दिन के लिए ही पूर्व ही श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों की भी उमड़ पड़ी। प्रशासन के अनुसार शनिवार शाम 6:00 बजे तक डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने संगम सहित गंगा के विभिन्न घाटों पर स्नान किया।

संगम किनारे तीन जनवरी 2026 से चल माघ मेले के सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान के ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय बताते हैं कि 17 जनवरी को रात 12 बजे से ही अमावस्या लग जाएगी लेकिन स्नान का पुण्य काल 18 जनवरी को सुबह 5 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलेगा। स्वामी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी का कहना है कि मौनी अमावस्या में मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान की धार्मिक परम्परा है। मौन रहकर जप तप और स्नान करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है इसलिए संगम में मौन रहकर पवित्र स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य अवसर पर त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए शनिवार सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। माघ मेला अधिकारी ऋषिराज बताते हैं कि शनिवार सुबह से दोपहर तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं। उनके मुताबिक मौनी अमावस्या में संगम और उसके आसपास के घाटों में 3 से 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। इसी अनुमान को देखते हैं प्रशासन ने खुद को तैयार किया है।

माघ मेला पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं की सकुशल पुण्य स्नान कराना मेला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। मेला अधिकारी ऋषिराज का कहना है कि इसके लिए मेला क्षेत्र में घाटों की विस्तारित किया गया है, 24 घाटों का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं को निकट के ही घाटों में स्नान कराने की व्यवस्था की गई है। भीड़ को लगातार सर्कुलेट करने के लिए जोन व्यवस्था का अनुपालन किया जा रहा है। इस बार 1000 वर्ग फीट सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है। जिस सेक्टर से जो आयेगा उसी सेक्टर में स्नान कराकर उसे वापसी के मार्ग से भेज दिया जाएगा। 42 स्थानों पर बनी पार्किंग के आगे दो या चार पहिया वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के पहले उमड़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए भीड़ प्रबंधन और उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। माघ मेला पुलिस प्रभारी नीरज पांडेय का कहना है कि संगम नोज में भीड़ के दबाव को देखते हुए सेफ्टी का विशेष मॉडल लागू किया गया है। इसके अंतर्गत संगम नोज में एक बिजली के पोल से दूसरे बिजली के पोल के बीच सुरक्षा कर्मी मुस्तैद रहेंगे। इस तरह अकेले संगम नोज और ऐरावत घाट में इसके लिए 650 से अधिक कर्मी तैनात रहेंगे। घाटों पर जल के अंदर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। एक तरफ जहां 15 हजार से अधिक पुलिस कर्मी इसके लिए तैनात रहेंगे तो वहीं जल पुलिस का सुरक्षा घेरा भी जल में सतर्क रहेगा।

बेबी कॉर्न को डाइट में शामिल करने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ

बेबी कॉर्न का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं। बेबी कॉर्न में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि बेबी कॉर्न के सेवन से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में है सहायक

बेबी कॉर्न में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में मददगार हो सकता है। फाइबर आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और कब्ज, गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकता है। इसके अतिरिक्त फाइबर भोजन को अच्छे से पचाने में भी मदद कर सकता है। इसके साथ ही बेबी कॉर्न का सेवन आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर पाचन क्रिया को सुधार सकता है।

वजन प्रबंधन में है मददगार

अगर आप वजन घटाने की कोशिश में लगे हैं तो इसके लिए भी बेबी कॉर्न का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसमें कम कैलोरी होती है और यह उच्च फाइबर युक्त होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इसके कारण आप बार-बार खाने से बच सकते हैं और वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी जलाता है।

आंखों की रोशनी के लिए है लाभदायक

आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी बेबी कॉर्न मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-ए और विटामिन-सी होता है, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। ये विटामिन आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के साथ-साथ आंखों की बीमारियों जैसे मोतियाबिंद और उम्र संबंधित दृष्टि हानि से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।

दिल को स्वस्थ रखने में है प्रभावी

बेबी कॉर्न का सेवन दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखते हैं। ये तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। इसके अलावा इनसे दिल की धड़कन भी नियमित रहती है। बेबी कॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो दिल की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं।

कैंसर से बचाव करने में है कारगर

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करने में भी बेबी कॉर्न फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में हानिकारक तत्वों को खत्म कर कैंसर के जोखिम कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर आंतरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए कैंसर से बचाव में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार बेबी कॉर्न का सेवन सेहत के लिए कई लाभकारी हो सकता है।

आपके घर के नजदीक हैं मोमोज–चाऊमीन की दुकानें तो डायबिटीज और मोटापे का खतरा ज्यादा : रिसर्च में दावा

मोमोज और चाऊमीन आपको डायबिटीज का शिकार बना सकते हैं। एक रिसर्च में ऐसा दावा किया गया है। फास्ट फूड डायबिटीज कैसे कर सकते हैं और क्यों रिसर्च में इनको इस बीमारी से जोड़ा गया है इस बारे में जानते हैं।

ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो सकती है ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोमोज और चाऊमीन भी इस बीमारी का कारण बन सकते हैं। अगर आपके घर या मोहल्ले के पास मोमोज और चाऊमीन जैसी फास्ट फूड की दुकानें हैं, तो यह सेहत को बिगाड़ सकता है। एक नई रिसर्च में दावा किया गया है। रिसर्च के मुताबिक, जिन इलाकों में मोमोज चाऊमीन जैसे फास्ट फूड आसानी से मिल जाते हैं वहां रहने वाले लोगों में टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे का रिस्क होता है।

आमतौर पर माना- जाता है कि फास्ट फूड पेट खराब करते हैं और कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, लेकिन इस रिसर्च में फास्ट फूड को डायबिटीज और मोटापे से जोड़ा गया है। यह रिसर्च एक संस्था ने चेन्नई के कई इलाकों में की है। यह पता चला है कि जिन लोगों के घर के 400 मीटर के अंदर फास्ट फूड की दुकानें हैं वहां के लोगों में डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बाहर खाने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो लोग घर का पौष्टिक भोजन छोड़कर बार-बार बाहर का खाना खाने लगते हैं। इससे कैलोरी इनटेक बढ़ता है शरीर में मोटापा भी बढ़ता है जो डायबिटीज का एक कारण है।

मोमोज और चाऊमीन क्यों हैं नुकसानदायक

मोमोज और चाऊमीन लोग बहुत खाते हैं, लेकिन इनमें बड़ी मात्रा में मैदा होती है। इसके अलावा ज्यादा नमक और रिफाइंड ऑयल भी होता है। इससे वजन बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल हो सकता है। ज्यादा नमक और तेल से दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।रिसर्च में यह भी बताया गया कि स्कूल-कॉलेज के आसपास फास्ट फूड स्टॉल होने से बच्चों और युवाओं में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। कम उम्र में बच्चे टाइप- 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं।रिसर्च में कहा गया है कि बच्चों में भी मोमोज खाने का ट्रेड बढ़ रहा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो हर दूसरे दिन इनको खा रहे हैं। ऐसे में इन बच्चों में इंसुलिन रजिस्टेंस गड़बड़ हो रहा है।

बचाव कैसे करें

फास्ट फूड का सेवन सीमित करें और इनको महीने में एक या दो बार से ज्यादा न खाएं।

घर के भोजन को खाएं

रोज एक्सरसाइज करेंट

पर्याप्त नींद लें

किस देश में सबसे ज्यादा शाकाहारी? जवाब सुनकर झूम उठेंगे भारतीय वेजिटेरियन

दुनिया भर में वेजिटेरियन्स की संख्या बढ़ रही है। जानवरों से लगाव, एनवायरमेंट में बदलाव और दूसरे कई कारणों की वजह से अब लोग शाकाहारी खानपान को ज्यादा फायदेमंद मानने लगे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किन देशों में सबसे ज्यादा शाकाहारी हैं। जानें क्या कहती है रिपोर्ट..

शाकाहारी होना अब सिर्फ खानपान की आदत नहीं है बल्कि ये लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाला लाइफस्टाइल ट्रेंड बन चुका है। ऐसी कई कारण हैं कि लोग वेजिटेरियन्स बनते जा रहे हैं। इसके पीछे हेल्थ, एनवायरमेंट में चेंज, कल्चर और नैतिक जैसे कई कारण काम कर रहे हैं। दुनिया भर लोग तेजी से वेजिटेरियन या प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ रूख कर रहे हैं। इसमें एक कारण मीट या दूसरे नॉनवेज फूड्स में मिलावट भी है। भारत या एशिया के कई देशों में चिकन के लिए सिर्फ 45 दिन में चूजे को बड़े मुर्गे में बदल दिया जाता है। एक फैक्टर स्टार्स को फॉलो करने का भी है। भारत में विराट कोहली जैसे बड़े स्टार्स वेगन डाइट को फॉलो करते हैं। कुछ लोग तो इसे वेजिटेरियन्स होने का फैशन तक बोलने लगे हैं। वैसे सोच को बदलने में वीडियो या सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है।

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने कई आंकड़े जुटाए हैं जहां वेजिटेरियन फूड खाने वालों की संख्या अब ज्यादा है। भले ही इन देशों के ट्रेडिशन और मान्यताएं अलग हैं लेकिन फिर भी यहां के लोग वेजिटेरियन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मॉर्डन दुनिया में अब नॉनवेज फूड्स आसानी से घर पहुंच सकते हैं। इसके बावजूद लोग वेजिटेरियन फूड्स को ज्यादा त्वज्जो दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से 7 देश हैं जहां वेजिटेरियन्स सबसे ज्यादा हैं।

भारत में 29.5 फीसदी

वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक भारत में करीब 29.5 फीसदी शाकाहारी हैं। देश में धार्मिक भावनाओं के कारण शाकाहारियों की संख्या ज्यादा है। यहां अब लोग एनिमल बेस्ड डाइट की जगह प्लांट बेस्ड डाइट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसमें दाल, सब्जियां और फर्मेंटेड फूड्स को खाना शामिल है। वैसे न्यूट्रिएंट्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत में काफी खाए जाते हैं।

मेक्सिको में 19 फीसदी

इस देश का ट्रेडिशनल खानपान मीट बेस्ड रहा है लेकिन यहां भी वेजिटेरियन्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां बीन्स, कॉर्न और सब्जियों को खाने का ट्रेंड बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए यहां वेजिटेरियन्स फूड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है।

ब्राजील में 14 फीसदी

ब्राजील की बात करें तो यहां की आबादी का करीब 14 फीसदी हिस्सा शाकाहारी खानपान को पसंद करता है। इसमें युवा और शहरी इलाकों के लोगों की संख्या ज्यादा है। बीते सालों में यहां शाकाहारी खानपान को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है। यहां की जगह चुर्रास्कों को एक समय पर नॉनवेज के लिए बहुत पसंद किया जाता था लेकिन यहां भी अब वेजिटेरियन्स की संख्या बढ़ रही है।

ताइवान में 13.5 फीसदी

इस देश का बौद्ध धर्म से खास कनेक्शन है और इस वजह से यहां मांसाहार से परहेज करने को बढ़ावा दिया जाता है। वैसे ताइवान में वेजिटेरियन्स की संख्या बढ़ रही है। ये देश वेजिटेरियन फूड कल्चर के लिए भी मशहूर है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में शाकाहारी रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड्स आसानी से देखने को मिल जाते हैं। शाकाहारी फूड्स की बात करें तो इसमें सोयाबीन और मशरूम फेमस है जिससे प्रोटीन जैसे कई तत्व आसानी से मिल जाते हैं।

इजरायल में 13 फीसदी

कहा जाता है कि इजरायल दुनिया के उन देशों में से एक है जहां वेजिटेरियन्स या वीगन के लिए एक अनुकूल माहौल है। यहां प्लांट वाली डाइट को फॉलो करने के पीछे कई कारण हैं। वैसे हम्मस, सलाद और मेजे जैसे कई वेजिटेरियन डिश हैं जिनका इजरायल से पुराना कनेक्शन है। इस देश में करीब 14 फीसदी लोग शाकाहारी हैं।

ऑस्ट्रेलिया में 12.1 फीसदी

इस विदेशी सरजमीं पर नॉनवेज खाने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है लेकिन यहां भी सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स को खाने का ट्रेंड है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट में चेंज और जानवरों के प्रति लगाव के कारण यहां शाकाहारी खाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस देश में करीब 12.1 फीसदी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी चीजें खाना ही पसंद करते हैं। यहां कई ऐसे कैफे, रेस्टोरेंट्स और किराना के स्टोर्स हैं जहां सिर्फ वेजिटेरियन्स चीजें ही मिलती हैं।

फिनलैंड में 12 फीसदी

साफ हवा और बेहतरीन नजारों के लिए दुनिया भर में मशहूर फिनलैंड में 12 फीसदी लोग ऐसे हैं जो खुद को वेजिटेरियन बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए लोग नॉनवेज फूड्स के दूरी बना रहे हैं। इतना ही नहीं सार्वजनिक खाद्य नीतियों के तहत यहां मांस के सेवन को कम करने पर बढ़ावा दिया जा रहा है।

क्या हैं किरायदारों के हक ? हर किसी के लिए जानना जरूरी

अगर आप भी किराए पर रहते हैं तो ये लेख आपके काम का है। यहां हम आपको आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे।

भारत में लाखों लोग किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन अधिकतर किरायदार अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होते हैं। कई बार मकान मालिक मनमानी शर्तें थोप देते हैं, अचानक घर खाली करने को कहते हैं या बिना सूचना किराया बढ़ा देते हैं। ऐसे में किरायदारों के लिए अपने हक जानना बेहद जरूरी हो जाता है।

अगर आप नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से किराए के मकान में रहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि किन हालात में मकान मालिक आपको निकाल सकता है और किन में नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का कानून किरायदारों को भी उतनी ही सुरक्षा देता है, जितनी मकान मालिकों को। बहुत से लोग इस अधिकारों से अनजान हैं, इसी के चलते इस लेख में हम आपको किरायदारों के अहम अधिकार आसान भाषा में बता रहे हैं।

रेंट एग्रीमेंट का अधिकार

किरायदार और मकान मालिक के बीच लिखित रेंट एग्रीमेंट होना कानूनी रूप से बेहद जरूरी है।

इसमें किराया, अवधि, नियम-शर्तें, डिपॉजिट और नोटिस पीरियड साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से भविष्य में विवाद की स्थिति में किरायदार को कानूनी सुरक्षा मिलती है।

नोटिस पीरियड

मकान मालिक बिना पूर्व सूचना के किरायदार को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

आमतौर पर 1 से 3 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है, जैसा कि रेंट एग्रीमेंट में तय होता है।

नोटिस पीरियड के बिना घर खाली कराना गैरकानूनी माना जाता है।

डिपॉजिट की वापसी

अगर किरायदार मकान को बिना किसी नुकसान के खाली करता है, तो मकान मालिक को पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटानी होती है।

केवल वैध कारणों और लिखित खर्चों के आधार पर ही कटौती की जा सकती है।

प्राइवेसी का अधिकार

किरायदार की अनुमति के बिना मकान मालिक घर में प्रवेश नहीं कर सकता।

ये किरायदार की निजता का उल्लंघन माना जाता है और कानून इसके खिलाफ सुरक्षा देता है।

मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकते

मकान मालिक किराया अचानक या मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता।

किराया बढ़ोतरी वही मान्य होती है जो रेंट एग्रीमेंट में लिखी गई हो।

बुनियादी सुविधाएं

पानी, बिजली, सीवरेज और जरूरी मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाएं देना मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है।

इन्हें जानबूझकर बंद करना अवैध है, और ऐसे समय में किरायदार पुलिस की मदद ले सकता है।

गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया? इन आसान तरीकों से वापस पाएं अपना पैसा

डिजिटल पेमेंट के दौर में यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग ने लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। अब चंद सेकंड में कहीं भी पैसा भेजा जा सकता है। लेकिन इसी तेजी के साथ एक समस्या भी बढ़ी है। गलत बैंक अकाउंट या गलत यूपीआई ID पर पैसे ट्रांसफर हो जाना। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सही तरीके से शिकायत करने पर पैसा वापस मिलने की संभावना रहती है।

पैसे भेजते समय लोग आमतौर पर अकाउंट नंबर, यूपीआई ID और नाम को कई बार चेक करते हैं, फिर भी कई बार छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है।

सबसे पहले करें ये काम

अगर आपने Google Pay, PhonePe, Paytm या BHIM जैसे किसी UPI ऐप से पेमेंट किया है, तो सबसे पहले उसी ऐप के कस्टमर केयर से संपर्क करें। ऐप में Help, Support या Report a Problem का विकल्प होता है। वहां जाकर गलत ट्रांजैक्शन को चुनें और शिकायत दर्ज करें। शिकायत करते समय ट्रांजैक्शन ID, UTR नंबर, तारीख और रकम जैसी जानकारी देना जरूरी होता है। इसके आधार पर ऐप की सपोर्ट टीम NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के जरिए रिफंड रिक्वेस्ट डालती है।

बैंक से भी कर सकते हैं संपर्क

अगर ऐप से बात करने के बाद भी समाधान न मिले, तो अगला कदम है अपने बैंक से संपर्क करना। आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक NPCI के माध्यम से विवाद दर्ज कर रिवर्सल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

NPCI की हेल्पलाइन पर करें कॉल

इसके अलावा, आप सीधे NPCI की हेल्पलाइन 1800-120-1740 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। NPCI की वेबसाइट पर मौजूद Dispute Redressal Mechanism सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत करने का विकल्प भी उपलब्ध है। यहां आपको ट्रांजैक्शन ID, UTR नंबर, भेजी गई रकम और दोनों UPI ID जैसी जानकारी देनी होती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, गलत ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद शिकायत करने से रिफंड मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए जैसे ही गलती का पता चले, देरी किए बिना ऐप, बैंक या NPCI से संपर्क करना सबसे बेहतर तरीका है। डिजिटल पेमेंट में सतर्कता जरूरी है, लेकिन अगर गलती हो भी जाए तो सही प्रक्रिया अपनाकर नुकसान से बचा जा सकता है।

ग्रीनलैंड की सुरक्षा अहम, एक फरवरी से डेनमार्क समेत आठ देशों पर लगेगा 10% टैरिफ: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घोषणा की कि अगले महीने से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से उनके देश भेजे जाने वाले सामानों पर दस फीसदी आयात शुल्क (टैरिफ) लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टैरिफ तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता।

ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर क्या कहा?

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय संघ (ईयू) के सभी सदस्य देशों और अन्य राष्ट्रों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे न तो शुल्क (टैरिफ) लिया और न ही किसी अन्य प्रकार का भुगतान। अब सदियों बाद समय आ गया है कि डेनमार्क कुछ वापस करे, क्योंकि विश्व शांति दांव पर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दो डॉग स्लेज (बर्फीले इलाके में कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी) हैं, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है।

उन्होंने आगे लिखा, इस स्थिति में केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका इस खेल में प्रभावी भूमिका निभा सकता है और वह भी पूरी सफलता के साथ। इस पवित्र भूमि को कोई नहीं छू सकता, खासकर तब जब अमेरिका और पूरी दुनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा इससे जुड़ी हो। इसके अलावा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड के लोग ग्रीनलैंड पहुंच रहे हैं, जिनके मकसद स्पष्ट नहीं हैं।

एक फरवरी से इन आठ देशों पर लगेगा टैरिफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, इसी कारण एक फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। एक जून 2026 से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह शुल्क तब तक लागू रहेगा, जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और अंतिम खरीद को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, अमेरिका पिछले 150 वर्षों से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रयास करता रहा है। कई राष्ट्रपतियों ने इसके लिए कोशिश की और इसके पीछे ठोस कारण भी थे, लेकिन डेनमार्क ने हमेशा इनकार किया। अब 'गोल्डन डोम' और आक्रामक और रक्षात्मक दोनों आधुनिक हथियार प्रणालियों के कारण इस भूमि को हासिल करना और भी जरूरी हो गया है।

डोम से जुड़े सुरक्षा कार्यक्रमों पर क्या बोले ट्रंप?

'डोम' से जुड़े सुरक्षा कार्यक्रमों पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में कनाडा की संभावित सुरक्षा भी शामिल है।

यह प्रणाली अत्यंत उन्नत और जटिल है।

प्रणाली तभी पूरी क्षमता और प्रभाव से काम कर सकती है, जब इसमें इस भूमि (ग्रीनलैंड) को शामिल किया जाए।

इसके लिए कोण, सीमाएं और भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण हैं।

ट्रंप ने कहा, अमेरिका तुरंत डेनमार्क और उन सभी देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार है, जिन्होंने इतना बड़ा जोखिम पैदा किया है, जबकि अमेरिका ने दशकों से उन्हें अधिकतम सुरक्षा और सहयोग दिया है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

भारत से दूरी अमेरिका को पड़ेगी भारी? टैरिफ पर रिपब्लिकन सांसद की चेतावनी ने बढ़ाई हलचल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर एक अहम बयान सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सांसद रिच मैककॉर्मिक ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने भारत को अलग-थलग किया, तो यह उसके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब व्यापार, टैरिफ और ऊर्जा खरीद को लेकर भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए मैककॉर्मिक ने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए भारत को अमेरिका के लिए कहीं अधिक अहम और भरोसेमंद साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ निवेश लेने वाला देश नहीं है, बल्कि अमेरिका में निवेश भी लाता है और प्रतिभा के रूप में बड़ी भूमिका निभाता है।

पाकिस्तान पर कही ये बात

रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी भले ही बड़ी हो, लेकिन वह अमेरिका के लिए न तो बड़े निवेश लाता है और न ही दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य। इसके उलट भारत अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश, तकनीकी प्रतिभा और नवाचार के जरिए मजबूत योगदान दे रहा है। उनके मुताबिक यही वजह है कि अमेरिका को भारत के साथ रिश्तों को संभलकर आगे बढ़ाना चाहिए।

ऊर्जा नीति पर भारत का रुख क्यों अलग है?

मैककॉर्मिक ने माना कि अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल खरीद से खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत की मजबूरी भी समझी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखते हैं। सस्ता तेल खरीदना भारत की आर्थिक जरूरत है और इसे उसी नजर से देखा जाना चाहिए। चर्चा के दौरान भारतीय मूल के डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने भी भारत के पक्ष को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की कोई गहरी रणनीतिक साझेदारी नहीं है, जबकि भारत में अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। इससे साफ है कि अमेरिका का भविष्य भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अंत में रिच मैककॉर्मिक ने ट्रंप प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका भारत को दोस्त की तरह अपनाता है तो शांति और समृद्धि मिलेगी। लेकिन अगर भारत को दूर किया गया, तो इसके नतीजे अमेरिका के लिए भी गंभीर होंगे।

टैरिफ और व्यापार तनाव का असर क्या है?

भारत और अमेरिका के बीच हाल के महीनों में व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा है।
अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं, जिससे कुल शुल्क काफी बढ़ गया है।
टैरिफ बढ़ने से दोनों देशों के व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है।
अमेरिका का आरोप है कि भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से यूक्रेन युद्ध में रूस को अप्रत्यक्ष मदद मिल रही है।
इसी मुद्दे के कारण भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की बातचीत फिलहाल रुकी हुई है।

गाजा 'शांति बोर्ड' से इस्राइल नाराज, यू-एस की घोषणा पर आपत्ति जताई, बताया पॉलिसी के खिलाफ

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) का गठन किया है। इसी के साथ 20 सूत्री शांति योजना के दूसरे चरण की देखरेख के लिए गठित 'शांति बोर्ड' में नियुक्त लोगों की सूची भी जारी की गई। जिस पर इस्राइल ने आपत्ति जताई है।

दरअसल, व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई लिस्ट में में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सीईओ मार्क रोवन और अमेरिका के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल को भी इस सूची में शामिल

किया गया है। हालांकि इस्राइल ने अमेरिकी नेताओं की घोषणा पर आपत्ति जताई है।

इस्राइल के साथ नहीं किया कोऑर्डिनेटेड

इस्राइल ने गाजा कार्यकारी समिति को लेकर कहा कि इस्राइल के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं था और यह उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि इसके बारे में अधिक जदानकारी नहीं दी गईं। बयान में यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेश मंत्रालय को विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क करने के लिए कहा है। दरअसल, शुक्रवार को व्हाइट हाउस द्वारा घोषित समिति में कोई इस्राइल अधिकारी नहीं है, लेकिन एक इस्राइल बिजनेसमैन है। अब तक घोषित अन्य सदस्यों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे करीबी विश्वासपात्र एक पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक अमेरिकी जनरल और मध्य पूर्वी सरकारों के शीर्ष अधिकारियों का एक समूह शामिल है।

देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

कोलकाता/गुवाहाटी। भारतीय रेलवे के इतिहास में शनिवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। यह ट्रेन न केवल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई रफ्तार देगी। पूरी तरह से वातानुकूलित 16 कोच वाली यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी।

हवाई जहाज जैसी सुविधाएं और 3 घंटे की बचत

इस आधुनिक ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गति और सुविधाएं हैं। यह ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच की लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को महज 14 घंटे में तय कर लेगी। मौजूदा समय में चलने वाली अन्य ट्रेनों की तुलना में यह करीब ढ़ाई से तीन घंटे कम समय लेगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाली इस ट्रेन में झटकों को कम करने के लिए बेहतरीन सस्पेंशन सिस्टम, ऑटोमैटिक दरवाजे और आरामदायक बर्थ लगाए गए हैं। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को क्षेत्रीय बंगाली और असमिया व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिलेगा।

किराये का गणित: 400 किमी का लगेगा न्यूनतम चार्ज

रेलवे बोर्ड ने इस प्रीमियम ट्रेन के लिए किराये का ढांचा भी तय कर दिया है, जो सामान्य ट्रेनों से काफी अलग है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस ट्रेन में न्यूनतम दूरी की सीमा 400 किलोमीटर तय की गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई यात्री 400 किलोमीटर से कम दूरी (जैसे 100 या 200 किमी) का भी सफर करता है, तो उसे पूरा 400 किलोमीटर का ही किराया देना होगा। एसी-3 टियर के लिए यात्रियों को कम से कम 960 रुपये, एसी-2 टियर के लिए 1,240 रुपये और एसी-1 (फर्स्ट क्लास) के लिए 1,520 रुपये चुकाने होंगे। यदि यात्रा 400 किलोमीटर से अधिक की है, तो उसके बाद एसी-1 के लिए 3.20 रुपये, एसी-2 के लिए 3.10 रुपये और एसी-3 के लिए 2.40 रुपये प्रति किलोमीटर के आधार पर शुल्क जुड़ेगा। इस किराये पर जीएसटी अलग से लागू होगा।

नहीं मिलेगा व्रश्ट टिकट, केवल कन्फर्म सीट का नियम

वंदे भारत स्लीपर में सफर करने वालों को बुकिंग के कड़े नियमों का पालन करना होगा। रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक, इस ट्रेन में रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन (व्रश्ट), वेटिंग लिस्ट या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकटों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे, यानी सफर के लिए पूरी बर्थ मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा, कोटे को भी सीमित किया गया है। ट्रेन में केवल महिला आरक्षण, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, वरिष्ठ नागरिक और ड्यूटी पास आरक्षण ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कोटा इस ट्रेन में लागू नहीं होगा।

ममता बनर्जी ने सीजेआई से की लोकतंत्र बचाने की अपील, केंद्रीय एजेंसियों पर उठाए सवाल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत से देश के संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की रक्षा करने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्रीय एजेंसियां लोगों को गलत तरीके से निशाना बना रही हैं, इससे उन्हें बचाया जाए।

ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के उद्घाटन समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने सीजेआई की मौजूदगी में कहा, 'कृपया संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास, भूगोल और देश की सीमाओं को आपदा से बचाएं। आप संविधान के रक्षक हैं और हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका में सीजेआई से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने देश की जनता की तरफ से अनुरोध किया कि जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी से एकता के लिए काम करने, बोलने और सोचने की अपील की। इस कार्यक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे।ममता का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में आई-पैक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और ईडी की कार्रवाई भी चर्चा में रही है।

विपक्ष का पलटवार

मुख्यमंत्री के बयान पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह उनकी हताशा को दिखाता है। वहीं, वरिष्ठ वकील विकास भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि ममता न्याय व्यवस्था को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि आम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है।

आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म एक दिन का पहला पोस्टर हुआ जारी, 1 मई को रिलीज होगी साई पल्लवी की फिल्म

महाराज और लवयापा जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत चुके जुनैद खान की आगामी बॉलीवुड फिल्म एक दिन का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म के पोस्टर के साथ निर्माताओं ने आज एक दिम की रिलीज की जानकारी शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है।

आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक दिन का पहला पोस्टर जारी किया। इसमें जुनैद खान और साई पल्लवी बर्फबारी में रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों बर्फबारी में कड़ाके की ठंड के बीच आइसक्रीम खाते दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, जिंदगी की उथल-पुथल में, प्यार तुम्हें ढूंढ लेगा... एक दिन।

फिल्म निर्माताओं ने एक दिन के फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ इसकी रिलीज डेट का भी एलान कर दिया है। एक दिन 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं फिल्म का पहला टीजर आज 16 जनवरी को जारी किया जाएगा।

एक दिन के डायेरक्टर सुनील पांडे हैं। एक दिन की कहानी स्नेहा देसाई और स्पनंद मिश्रा ने लिखी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मंसूर खान, आमिर खान और अपर्णा पुरोहित हैं। म्यूजिक राम संपत का है। लिरिक्स इरशाद कामिल के हैं। यह जुनैद की तीसरी फिल्म है। इससे पहले जुनैद महाराज और लवयापा में नजर आ चुके हैं। साई पल्लवी साउथ एक्ट्रेस हैं। वो रणबीर कपूर के साथ रामायण में नजर आएंगी।

जब 4 साल की उम्र में फातिमा सना शेख को सेट पर पड़ी थी जोरदार डांट, संघर्ष के साथ तय किया फिल्मी सफर

दंगल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली सना शेख बचपन में ही बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। उन्होंने कमल हासन और तब्बू अभिनीत 1997 की हिट फिल्म चाची 420 में कमल हासन की बेटी का रोल प्ले किया था

बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख छोटी उम्र से ही इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं और इसलिए उन्होंने सब कुछ देखा है। कुछ ऐसी चीजें भी जो एक बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। उनके अनुभवों ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया, लेकिन उनके अंदर की मासूमियत आज भी जिंदा है। फातिमा सना शेख ने 4 साल की उम्र से करियर की शुरुआत की और टीवी की जर्नी से होते हुए बॉलीवुड में एंट्री ली। हालांकि बचपन में उन्हें शूटिंग सेट पर काफी कुछ झेलना पड़ता था। दंगल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली सना शेख बचपन में ही बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। उन्होंने कमल हासन और तब्बू अभिनीत 1997 की हिट फिल्म चाची 420 में कमल हासन की बेटी का रोल प्ले किया था। सना ने खुद खुलासा किया था कि उस वक्त बच्चों को क्या ही पता होता है और जो बोला जाता है, बच्चे अपने मूड के हिसाब से करते हैं। ऐसा ही कुछ चाची 420 के सेट पर हुआ और उन्हें रोने के लिए कहा गया। अभिनेत्री ने बताया था कि उस वक्त उन्होंने नकली रोना शुरू किया और थोड़ा सा मुंह बना लिया, लेकिन सीन को परफेक्ट बनाना था और तभी किसी ने मुझे जोरदार डांट लगाई और मैं सच में रोने लगी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही रोना चाहिए था।

सना को ऐसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनसे किसी बच्चे को नहीं गुजरना चाहिए। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सेट पर 15 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था और उस वक्त बाल कलाकारों के लिए नियम और सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं थी। वे सेट पर बड़ों लोगों की ऐसी बातें सुनती थी, जो बच्चों को नहीं सुननी चाहिए।

फातिमा ने आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में हाथ आजमाया। फिल्मों में सहायक भूमिकाओं के अलावा, उन्होंने कुछ टेलीविजन शो भी किए। वे फिल्मों में आने से पहले सीरियल अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो में नजर आईं, जहां उन्होंने सुमन का किरदार निभाया। इसके अलावा वे लेडीज स्पेशल शो में भी दिखाई दीं।

बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि साल 2016 में दंगल से डेब्यू करने से पहले कई फिल्मों में साइड रोल कर चुकी थी। उन्हें साल 2008 में आई तहान, 2013 में आई आकाश वाणी और 2012 बिट्टू बॉस में छोटे-मोटे रोल में देखा गया था, लेकिन फिल्म दंगल से उनके करियर को बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस लूडो, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आप जैसा कोई और मेट्रो इन दिनों में देखा गया और अब वे रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क में दिख रही हैं।

बॉर्डर 2 का देशभक्ति से भरा ट्रेलर रिलीज, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान

साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में शामिल 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस वॉर ड्रामा का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब रिलीज से एक हफ्ते पहले मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर जारी किया है।

फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जब भारत की सेना, नौसेना और वायु सेना एक साथ मिलकर लड़ती हैं। 3 मिनट 35 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत में दिखता है कि सनी देओल पर पाकिस्तानी सेना तोप तान देती है। लेकिन सनी देओल की आंखों में डर की जगह जोश और जज्बा दिखता है। इसके बाद सनी देओल की दमदार आवाज में डायलॉगबाजी शुरू होती है। जिसमें सनी देओल कहते हैं, 'फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है। बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। न ही दुश्मन, न ही उसकी गोली और न ही उसका इरादा।' ट्रेलर में सनी देओल दमदार डायलॉगबाजी करते और जवानों में जोश भरते नजर आते हैं। उनका किरदार काफी हद तक 'बॉर्डर' के किरदार की ही तरह है।

इसके बाद ट्रेलर में एंट्री होती है वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की। वरुण धवन थल सेना में हैं, दिलजीत वायु सेना और अहान नेवी ऑफिसर के किरदार में हैं। ट्रेलर में सनी देओल के अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी डायलॉग मारते नजर आते हैं। युद्ध की कहानी और भारतीय सेना की वीरता को दिखाते इस ट्रेलर में फिल्म के सभी किरदारों की झलक दिखती है। ट्रेलर में अहान शेट्टी के खाते में डायलॉग कम हैं। ट्रेलर में तीनों सेनाओं के जज्बे को दिखाया गया है। लेकिन ट्रेलर प्रमुख रूप से ध्यान सनी देओल पर केंद्रित है।

ट्रेलर में जज्बे और हौसले के साथ इमोशन को भी दिखाया गया है। फौजियों के परिवार की झलक भी दिखाई गई है। कैसे जब एक फौजी जंग पर जाता है, तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। ट्रेलर में फिल्म की फीमेल एक्ट्रेस सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा की झलक भी दिखती है। हालांकि, आन्या सिंह ट्रेलर में नजर नहीं आती हैं।

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और जेपी दत्ता द्वारा प्रोड्यूस की गई ये 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। फिल्म साल 2026 की पहली बड़ी फिल्म है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com